राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण गुरूवार 26 नवंबर 2026 वर्ष-9,अंक-291 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

19934 करोड़ के प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी

पांच सेक्टर्स को होगा बड़ा फायदा अन्य प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी



नई दिल्ली (एजेंसी)। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए टनल बोरिंग मशीन या टीबीएम बेहद जरूरी उपकरण है। अभी इसका आयात करना होता है।

आने वाले दिनों में इसका निर्माण भारत में ही होगा। यही नहीं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े बड़े इक्विपमेंट भी अब देश में ही बनेंगे। इसके इकोसिस्टम विकसित करने लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपये की योजना को हरी झंडी दी है। इसके साथ ही चार अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार ने करीब 20,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव हो हरी झंडी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया।

बंदरगाह के लिए 4,288 करोड़

मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के कामराजार बंदरगाह में दूसरे कंटेनर टर्मिनल के डेवलपमेंट के लिए कुल 4,288 करोड़ रुपये की परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के बंदरगाहों ने 25.7 मिलियन (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स) हैंडलिंग की, जो वित्त वर्ष 2019-20 में 17.2 मिलियन टीईयू ही थी। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2025-26 तक सभी बंदरगाहों के कंटेनर ट्रैफिक में 6.9 फीसदी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की वृद्धि हुई है। कामराजार पोर्ट लिमिटेड का कंटेनर 9 से 11 फीसदी की दर से बढ़ रहा है।

राहुल की संपत्ति की सीबीआई-ईडी से जांच का आदेश रद्द

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राहुल गांधी की जांच का आदेश रद्द कर दिया। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को दिया था। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मामला फिर हाईकोर्ट भेज दिया। हाईकोर्ट अब राहुल गांधी को पक्ष बनाएगा और उनका पक्ष सुनने के बाद नया आदेश देगा। मई में हाईकोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की शिकायत पर सीबीआई और ईडी को आरोपों की जांच के निर्देश दिए थे। शिशिर ने राहुल गांधी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ जांच की मांग की थी। राहुल गांधी ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ता का इस मामले में कोई अधिकार नहीं है और उसने अपनी पहचान या योग्यता भी नहीं बताई है।



भारत-चीन समेत 16 देशों पर टैरिफ बढ़ा सकता है अमेरिका

सस्ते विदेशी सामान से यूएस की कंपनियों को नुकसान का आरोप

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका इसी हफ्ते भारत, चीन समेत 16 देशों से आने वाले सामान पर इसी हफ्ते टैरिफ बढ़ा सकता है। आरोप है कि ये देश सरकारी मदद से जरूरत से ज्यादा सामान बना रहे हैं और इन्हें सस्ते दामों पर बेच रहे हैं। इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर इस मामले में 11 मार्च से चल रही जांच के नतीजे जारी कर सकते हैं। यह जांच 1974 के अमेरिकी व्यापार कानून के तहत हो रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका दूसरे देशों के सामान पर अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है। हालांकि, टैरिफ की नई दरें अभी तय नहीं हुई हैं। अमेरिकी ने इसी साल फरवरी में टैरिफ दर घटाकर 18 कर दी थी।



जबरन मजदूरी के मामले में भी टैरिफ की तैयारी

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने जुलाई में विदेशी सप्लाई चेन में जबरन मजदूरी को लेकर भी जांच पूरी की थी। कार्यालय के मुताबिक, इस मामले में कई व्यापारिक साझेदार देशों पर 10 से 12.5 फीसदी तक अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। दोनों देशों ने फरवरी में समझौते की रूपरेखा तय की थी। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल लगाए गए टैरिफ रद्द किए जाने के कारण बातचीत बंद थी।

हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए,तीन डिजिट से कम मंजूर नहीं

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गुरुवार को लखनऊ में प्रस्तावित संविधान बचाओ यात्रा की तैयारी को लेकर लखनऊ में जुटे पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की सीटों के बंटवारे को लेकर फायर हैं।



सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद के बाद अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का गुस्से वाला बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की सीटों की संख्या पर बात फाइनल होने से पहले ही सपा की उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने पर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि सीटों की घोषणा कभी भी की जा सकती है।

राजनीति सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले-पूर्व राष्ट्रपति ने की थी चर्चा

प्रणब मुखर्जी ने दी थी बीजेपी में जाने की सलाह

पूछा था-टीएमसी में कर्मचारी बने रहना है या आगे बढ़ना है

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें टीएमसी छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के साथ आने की सलाह दी थी। उन्होंने मंगलवार को कोलकाता में एक समिट के दौरान यह बात कही। शुभेंदु के मुताबिक, राष्ट्रपति बनने के बाद जब वे प्रणब मुखर्जी से मिलने राष्ट्रपति भवन गए थे, तब दोनों के बीच यह बातचीत हुई थी।

शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि प्रणब मुखर्जी ने उनसे कहा था, सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर कर्मचारी बनकर रहना चाहते हैं तो यहीं रहिए। अगर अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मोदीजी के साथ रहिए। अधिकारी ने प्रणब मुखर्जी को अपना ओरिजिनल एडवाइजर बताया। उन्होंने कहा कि मुखर्जी उनके अभिभावक की तरह थे। राजनीति से अलग भी हर भारतीय उनका सम्मान करता है। प्रणब मुखर्जी का अगस्त 2020 में निधन हुआ था।



बातचीत की तारीख बताने से इनकार किया

जब शुभेंदु से पूछा गया कि प्रणब मुखर्जी के साथ यह बातचीत कब हुई थी, तो उन्होंने तारीख बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके बयान से विवाद हो सकता है, इसलिए वे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। शुभेंदु ने प्रणब मुखर्जी की एक और टिप्पणी का जिक्र किया। उनके मुताबिक, मुखर्जी ने पार्टी को बुआ-भतीजे की जोड़ी से चलने वाली पार्टी बताया था। यह टिप्पणी ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के संदर्भ में थी। शुभेंदु अधिकारी पहले ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। एक समय उन्हें टीएमसी में ममता के बाद सबसे ताकतवर नेताओं में गिना जाता था। शुभेंदु ने 2009 और 2014 में तमलुक लोकसभा सीट से चुनाव जीता। 2016 में नंदीग्राम से विधायक बने और ममता सरकार में परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। उनके पास पर्यावरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी था। वे कई जिलों में पार्टी के चुनावी अभियान और संगठन की जिम्मेदारी भी संभालते थे। हालांकि, पार्टी में अभिषेक बनर्जी का कद बढ़ने के साथ शुभेंदु और टीएमसी नेतृत्व के बीच मतभेद बढ़ने लगे। अभिषेक को ममता का उत्तराधिकारी माना जाने लगा था।

ऑपरेशन सिंदूर में भारत पर 3-चीनी सैटेलाइट की थी नजर

दावा-4 दिन भुज,जामनगर और रिलायंस रिफाइनरी की एक्टिविटी देखी

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 चीनी सैटेलाइट भारत के पश्चिमी तट पर लगातार नजर रख रहे थे। इन सैटेलाइट्स ने 4 दिन भुज, नलिया, जामनगर और रिलायंस रिफाइनरी की एक्टिविटी देखी। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में भारतीय स्पेस सर्विलांस और इंटेलिजेंस कंपनी डिगांतारा के हवाले से यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सैटेलाइट्स ने भारत के नौसैनिक और वायुसेना ठिकानों की निगरानी की। पोर्ट और महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया की भी निगरानी की गई। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू हुआ था और चार दिन चला था। इसी दिन इन सैटेलाइट्स ने अपनी कक्षा बदली थी।



दीपम विवाद! तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी माफी,कहा-मंदिर ट्रस्ट ने रोका

कोर्ट के आदेश के बावजूद स्तंभ पर नहीं जला दीप

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने के विवाद को लेकर राज्य सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। मदुरै कलेक्टर ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया कि सरकार ने दीपथून यानी पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की पूरी कोशिश की लेकिन देवस्थानम यानी मंदिर प्रशासन ने उसे रोका। सरकार के मुताबिक, मंदिर प्रशासन का कहना था कि दीपथून पर दीप जलाना स्थापित परंपराओं और धार्मिक रीति-रिवाजों के खिलाफ है। इसलिए दीप केवल उच पिल्लैयार मंदिर के पास पारंपरिक स्थान पर जलाया गया। 20 नवंबर को कोर्ट ने आदेश दिया था।

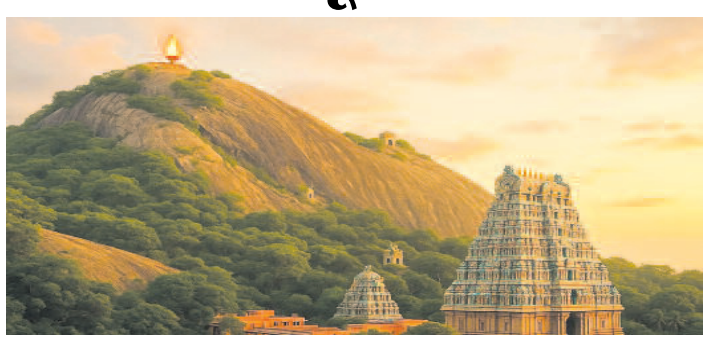

बीजेपी और हिंदू संगठनों के करीब 300 सदस्यों के खिलाफ केस

कार्तिगई दीपम विवाद के बीच मंगलवार को बीजेपी और हिंदू संगठनों ने राज्य भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 300 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। रामनाथपुरम में हिंदू फ्रंट के सदस्यों ने सड़क जाम कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

पहाड़ी पर लगातार दूसरे दिन आम लोगों की एंट्री बंद

विवाद के बाद बुधवार को लगातार दूसरे दिन श्रद्धालुओं और आम लोगों को तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर जाने से रोका गया। पलानी अंडावर मंदिर के प्रवेश द्वार के पास भारी पुलिस बल तैनात रहा। पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई। स्थानीय लोगों को भी जांच के बाद ही जाने दिया गया। पहाड़ी पर सुरक्षा व्यवस्था 23 नवंबर की शाम 6 बजे से लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति देते हुए आम लोगों, जुलूस और भीड़ को वहां जाने से रोकने का निर्देश दिया था। यह व्यवस्था कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक बार दीप जलाने की इजाजत दी थी

तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दीपथून यानी पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने को लेकर अरुलमिगु सुब्रमणिया स्वामी मंदिर और सिकंदर बदूशा दरगाह के बीच लंबे समय से विवाद है। मंदिर पहाड़ी के नीचे स्थित है, जबकि दरगाह और दीपथून पहाड़ी पर हैं। हिंदू संगठन दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की मांग करते रहे हैं। वहीं, दरगाह के पास होने के कारण इस मांग का विरोध होता रहा है। पुराने अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक, 1862 और 1912 में भी दीपथून पर दीप जलाने की कोशिश हुई थी। दोनों बार अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को इस साल 24 नवंबर को दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की एक बार की अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा था कि मंदिर प्रशासन की टीम अधिकारियों की निगरानी में दीप जलाएगी। आम लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि यह अनुमति केवल इस साल के लिए है।

आईपीएस अफसरों की पार्टी में मारपीट

डीआईजी के वार से एसएसपी घायल
वजह साफ नहीं सीएम हिमंता बोले-
यह अफसरों का निजी मामला है



दिसपुर (एजेंसी)। असम के कोकराझार में एक पार्टी के दौरान दो आईपीएस अफसरों के बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि किसी बात पर हुई बहस के बाद कोकराझार के एसएसपी अक्षत गर्ग और डीआईजी वाईटी गेत्सु आपस में भिड़ गए। हाथापाई में एसएसपी गर्ग को कई चोटें आई हैं। पार्टी 7वीं बटालियन के परिसर में आयोजित की गई थी।

दिनमें सीएम ने दी अनुशासन की सीख, रात में झगड़ा

यह घटना उस दिन सामने आई, जब मुख्यमंत्री ने डेरगांव स्थित लाचित बोरफुकन पुलिस अकादमी में नए भर्ती पुलिसकर्मियों की पासिंग आउट परेड को संबोधित किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को अनुशासन बनाए रखने, नशे से दूर रहने और गाली-गलौज या अनुचित भाषा का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी। सीएम ने कहा कि पुलिसकर्मियों के शब्दों, व्यवहार और काम में वर्दी की गरिमा और जिम्मेदारी झलकनी चाहिए।

सीएम ने डीजीपी को सौंपी सुलह की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम के डीजीपी को विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी दी। डीजीपी ने वरिष्ठ अधिकारी सुरेंद्र कुमार को दोनों अफसरों के बीच विवाद सुलझाने के लिए हस्तक्षेप करने को कहा है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि एसएसपी गर्ग को कितनी चोटें आई हैं।

सरकार ने दलाई लामा को लुटियंस जोन में दिया बंगला

यह घर पंडित रविशंकर शुक्ल लेन पर,विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर हुआ आवंटन

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने तिब्बती आध्यात्मिक गुरु 14वें दलाई लामा को नई दिल्ली के लुटियंस इलाके में सरकारी बंगला आवंटित किया है। यह बंगला पंडित रविशंकर शुक्ल लेन पर स्थित है। दलाई लामा के निजी कार्यालय गादेन फोद्रंग ट्रस्ट को विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर टाइप-7 बंगला दिया गया है। हालांकि, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस आवंटन पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ऐसे सरकारी आवास आमतौर पर तीन साल के लिए आवंटित किए जाते हैं, जिन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। यह बंगला दिल्ली में संसद से करीब तीन किलोमीटर दूर है। तिब्बती संसद-इन-एक्साइल ने इस फैसले के लिए भारत सरकार का आभार जताया है। संसद की अध्यक्ष डोलमा त्सेरिंग ने कहा कि यह दलाई लामा और तिब्बती समुदाय के प्रति भारत के समर्थन का महत्वपूर्ण संकेत है।



भारत में ओलंपिक कराने पर

जनता की राय लेगा आईओसी

मकसद यह जानना कि भारतीयों की इवेंट में रुचि है या नहीं,दिसंबर में सर्वे

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की 2036 ओलिंपिक की मेजबानी की दावेदारी के बीच इंटरनेशनल ओलिंपिक कमेटी दिसंबर में देश में सर्वे कराएगी। इसके जरिए यह जानने की कोशिश होगी कि भारत में ओलिंपिक कराने को लेकर आम लोगों की क्या राय है। लोग इस आयोजन को किस नजरिए से देखते हैं और क्या उन्हें लगता है कि ओलिंपिक की मेजबानी से देश में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी और खेलों को बढ़ावा मिलेगा। इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन के एक सूत्र ने बताया कि यह सर्वे दिसंबर में होगा, लेकिन किस-किस जगह के आईओसी के निर्धारित एजेंसी के लोग सर्वे के लिए जाएंगे, यह गुप्त है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। यह सर्वे भारत की दावेदारी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि देश के लोग कितने उत्साहित हैं।



अहमदाबाद में ओलिंपिक कराने की भारत की दावेदारी

भारत ने 2036 ओलिंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की है। भारत की योजना गुजरात के अहमदाबाद में ओलिंपिक आयोजित कराने की है। इसके लिए अहमदाबाद को मुख्य आयोजन स्थल के रूप में पेश किया जा रहा है। भारत का तर्क है कि देश में बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी करने की क्षमता और बुनियादी ढांचे को लगातार विकसित किया जा रहा है। ओलिंपिक से पहले गुजरात 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। इन खेलों का आयोजन अहमदाबाद में होना है। भारत के लिए यह आयोजन बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल इवेंट की मेजबानी के लिहाज से अहम होगा।

26 नवंबर को आईओसी के सामने भारत रखेगा दावेदारी के तर्क

2036 ओलिंपिक की मेजबानी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए सात देशों में भारत भी शामिल है। 26 नवंबर को आईओसी के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें भारतीय ओलिंपिक संघ भारत में, खास तौर पर गुजरात में, ओलिंपिक कराने को लेकर अपनी दावेदारी के पक्ष में तर्क रखेगा। इस बैठक में भारतीय खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, गुजरात खेल मंत्रालय और भारतीय ओलिंपिक संघ के अधिकारी शामिल होंगे।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संविधान गौरव दिवस : राष्ट्र की गरिमा, नागरिक अधिकार और कर्तव्य का संकल्प

(लेखक- सुरेन्द्र शर्मा)

(26 नवंबर संविधान गौरव दिवस पर विशेष)

26 नवंबर भारतीय लोकतंत्र की गौरवशाली तिथि है। इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया। इसके अधिकांश प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुए और भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना। संविधान दिवस हमें स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का स्मरण कराता है। यह नागरिक अधिकारों को समझने तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संकल्प लेने का अवसर है।

स्वतंत्रता के समय हमारा देश विभाजन की त्रासदी, सामाजिक विषमता, आर्थिक अभाव और निरक्षरता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा था। ऐसी परिस्थितियों में संविधान निर्माताओं ने न्याय, समानता और लोकतंत्र पर आधारित व्यवस्था चुनी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर सहित अनेक सदस्यों ने चर्चा, संशोधन और सहमति से संविधान निर्माण की ऐतिहासिक जिम्मेदारी पूरी की। विभिन्न विचारों और अनुभवों का यह समन्वय लोकतांत्रिक संवाद की शक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण है।

संविधान के निर्माण में बाबासाहेब भीमराव रामजी आंबेडकर का योगदान विशेष रूप से वंदनीय है। सामाजिक भेदभाव की पीड़ा से परिचित होने के कारण व्यक्ति की गरिमा, समान अवसर और वंचितों के अधिकार उनके चिंतन के केंद्र में रहे। बाबा साहेब के प्रति सच्ची श्रद्धा तभी होगी, जब हम अपने व्यवहार से छुआछूत, जातिगत अहंकार और सामाजिक अपमान दूर करेंगे। शिक्षा और लोकतांत्रिक प्रयासों से परिवर्तन लाने का उनका संदेश आज भी प्रेरक है।

संविधान की प्रस्तावना का आरंभ 卐हम, भारत के लोग卐 से होता है। ये शब्द बताते हैं कि संवैधानिक सत्ता का मूल स्रोत जनता है। प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त करती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता इसके प्रमुख आदर्श हैं। बंधुता व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने की प्रेरणा देती है।

भारतीय लोकतंत्र की शक्ति जागरूक नागरिक हैं। मतदान देश की दिशा निर्धारित करने में हमारी भागीदारी है, इसलिए निर्णय जानकारी, विवेक और सार्वजनिक हित के आधार पर होना चाहिए।

मौलिक अधिकार सम्मानपूर्ण जीवन का आधार हैं। इनका वास्तविक महत्व तब दिखाई देता है, जब कमजोर व्यक्ति भी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सके और न्याय प्राप्त कर सके। असहमति लोकतांत्रिक संवाद का स्वाभाविक अंग है; आलोचना को शत्रुता में बदलने से सामाजिक विश्वास कमजोर होता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की गरिमा के साथ उनकी जवाबदेही भी आवश्यक है। सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का आचरण पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए यह शिक्षा हमें संविधान ने दी है।

नागरिक कर्तव्यों में संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, देश की एकता की रक्षा, सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा शामिल हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना भी समाज को आगे बढ़ाते हैं। हमारी भाषाओं, आस्थाओं और परंपराओं की विविधता राष्ट्रीय संपदा है। किसी की पहचान के आधार पर अपमान या घृणा फैलाना इस साझा विरासत को चोट पहुँचाता है।

वर्ष 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान की भावना को 卐ष्ठद्वद्दट्ठद्वह्ल4 स्रश्ह्र ढ्ढट्ठस्रद्वड्डट्ठ ड्डट्ठस्र ट्ठद्वह्ल4 द्वश्ह्र ढ्ढट्ठस्रद्वड्डस्र अर्थात प्रत्येक भारतीय की गरिमा और भारत की एकता से जोड़ा है। उनके अनुसार अधिकारों और कर्तव्यों का अटूट संबंध है। यातायात नियमों का पालन, जल संरक्षण और समय पर कर भुगतान जैसे दैनिक कार्यों में भी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी प्रकट होती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान को वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक बताते हुए विकसित भारत के निर्माण पर बल दिया है। उन्होंने सामान्य पृष्ठभूमि के नागरिकों को आगे बढ़ने की शक्ति देने में संविधान की भूमिका रेखांकित की। पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं का सम्मान करने का उनका सुझाव नई पीढ़ी में लोकतांत्रिक भागीदारी और दायित्व की भावना बढ़ाने का अवसर है।

संविधान का गौरव मनाते समय उसके उल्लंघन के इतिहास से सीखना भी आवश्यक है। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाया गया 1975 का आपातकाल नागरिक स्वतंत्रताओं पर गंभीर प्रहार था। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियाँ, प्रेस पर सेंसरशिप और कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन पर प्रतिबंध सत्ता के केंद्रीकरण के खतरों की चेतावनी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन घटनाओं के संदर्भ में कांग्रेस पर संवैधानिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक स्वार्थ के लिए कमजोर करने वाला बताया है।

आपातकाल के दौरान 39वें संशोधन से इंदिरा गांधी के चुनाव को विशेष संरक्षण देने वाले प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक ठहराया। 42वें संशोधन द्वारा संसद की संशोधन शक्ति को असीमित करने और संविधान संशोधनों की न्यायिक समीक्षा रोकने के प्रयास भी हुए। 'मिनर्वा मिल्स' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित प्रावधान निरस्त किए। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय 2005 में बिहार विधानसभा का विघटन भी असंवैधानिक घोषित हुआ। ये घटनाएँ बताती हैं कि संवैधानिक सीमाओं का पालन प्रत्येक सरकार के लिए अनिवार्य है।

संविधान गौरव दिवस मनाना तभी सार्थक होगा, जब संविधान का सम्मान हमारे आचरण, और सार्वजनिक जीवन में दिखाई दे।

7 जून 2024 को नई दिल्ली स्थित संविधान सदन, अर्थात पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय संविधान की प्रति के समक्ष शीश झुकाया और उसे उठाकर श्रद्धापूर्वक अपने माथे से लगाया था लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया के बीच हुआ यह क्षण संविधान के प्रति सम्मान की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति था।

इस दृश्य का संदेश गहरा है—लोकतंत्र में प्रत्येक पद की गरिमा संविधान से आती है और उसके साथ जनता के प्रति उत्तरदायित्व भी जुड़ा होता है। संविधान को नमन करना उसके निर्माताओं की दूरदृष्टि, स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष तथा देशवासियों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के प्रति आदर प्रकट करना है।

संविधान का सम्मान तभी सार्थक होता है, जब उसके आदर्श हमारे आचरण में दिखाई दें। प्रधानमंत्री जी का यह भावपूर्ण नमन हमें इसी संकल्प की प्रेरणा देता है।

संविधान का सम्मान जेब में किताब रखने से नहीं, उसके आदर्शों पर चलने से होता है

संविधान की पुस्तक साथ रखना अच्छी बात है। लेकिन जो लोग इसे लेकर घूमते हैं, उनसे देश यह अपेक्षा भी करता है कि उनके व्यवहार, निर्णय और सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक मूल्यों का सम्मान दिखाई दे। संविधान के प्रति निष्ठा का प्रमाण केवल उसकी प्रति दिखाने से नहीं मिलता; वह अपने आचरण से देना पड़ता है। भारत का संविधान किसी एक दल, परिवार या विचारधारा की संपत्ति नहीं है। यह स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों, संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि और करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं का साझा दस्तावेज है। इसलिए इसे राजनीतिक मंच पर उठाने वाले हर व्यक्ति को उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए।

संविधान अधिकार देता है, तो कर्तव्य का बोध भी कराता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की शक्ति है। सरकार से प्रश्न पूछना, नीतियों की आलोचना करना और शांतिपूर्ण विरोध करना लोकतांत्रिक जीवन के आवश्यक अंग हैं। लेकिन इसी स्वतंत्रता के साथ तथ्यों के प्रति ईमानदारी, दूसरों की गरिमा का सम्मान और सार्वजनिक शांति की जिम्मेदारी भी जुड़ी है। अपने लिए स्वतंत्रता माँगते हुए विरोधी की आवाज दबाना संवैधानिक भावना के अनुरूप कैसे हो सकता है?

इसी तरह, समानता की बात करने वालों को अपने संगठन और व्यवहार में भी समान अवसर देने चाहिए। सामाजिक न्याय का दावा तभी विश्वसनीय बनता है, जब वंचित व्यक्ति को सम्मान, प्रतिनिधित्व और आगे बढ़ने का वास्तविक अवसर मिले। संविधान का नाम लेकर समाज में अविश्वास बढ़ाने से उसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती।

लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति रवैया भी एक महत्वपूर्ण कसौटी है।किसी संस्था का निर्णय अपने पक्ष में आए तो उसकी प्रशंसा करना और प्रतिकूल आए तो बिना ठोस आधार उसके अस्तित्व या नीयत पर प्रश्नचिह्न लगा देना सुविधाजनक राजनीति हो सकती है, संवैधानिक प्रतिबद्धता नहीं। संस्थाओं के निर्णयों की समीक्षा और आलोचना होनी चाहिए। त्रुटियों के विरुद्ध उपलब्ध प्रक्रियाओं का उपयोग भी होना चाहिए। लेकिन आरोप प्रमाण पर आधारित हों और सुधार का उद्देश्य संस्थाओं को अधिक निष्पक्ष तथा जवाबदेह बनाना हो।

जनादेश के प्रति भी यही दृष्टि आवश्यक है। चुनाव में जीत जनता की सेवा का अवसर है और हार आत्ममंथन का संदेश। चुनावी प्रक्रिया पर किसी आपत्ति को तथ्यों और निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से उठाना उचित है। केवल राजनीतिक असहमति के कारण मतदाताओं के निर्णय को तुच्छ बताना जनता के विवेक का अपमान है।

यह कसौटी सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए—सत्ता पक्ष पर भी और विपक्ष पर भी। संविधान का सम्मान तभी सार्थक है, जब हम अपने पक्ष की गलती पर भी प्रश्न उठाने का साहस रखें।

इसलिए जेब में संविधान की किताब लेकर घूमने वालों से प्रश्न पूछना आवश्यक है- क्या आपके आचरण में भी संविधान बसता है? क्या आपकी राजनीति में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के लिए जगह है? क्या आप वही मर्यादा अपने लिए स्वीकार करते हैं, जिसकी अपेक्षा दूसरों से करते हैं?

संपादकीय

भाजपा- अकाली पुनर्मिलन

पिछले कुछ महीनों से पंजाब व दिल्ली में भाजपा व अकाली दल की तरफ से जिस तरह की बयानबाजियां और राजनीतिक हलचल सामने आ रही थी, उसके निहितार्थ स्पष्ट ही थे। जो संकेत दे रहे थे कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का फिर एक बार साथ आना लगभग तय ही है। वर्ष 2027 के आसन्न पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन दोनों दलों का साथ आने का फैसला बताता है कि यह गठबंधन सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को चुनौती देने के ठोस प्रयास कर कर रहा है। इस गठबंधन की घोषणा गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर की गई है, जिसके ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक, दोनों ही तरह के महत्व हैं। यहां उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ने पहली बार तीन दशक पहले भी हाथ मिलाया था। उस समय इस गठबंधन को आतंकवाद से उबरते पंजाब में हिंदू-सिख एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। कालांतर दोनों दलों के रिश्तों में खटास उस समय आई, जब केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन विवादित कानूनों के विरोध में व्यापक जनाक्रोश दिखा। किसानों के आक्रोश के चलते अकाली दल को अपना जनाधार खिसकता नजर आया था। कालांतर वर्ष 2020 में अकाली दल ने भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़ लिया था। बहरहाल, इस गठबंधन की घोषणा के बाद जिस तरह के बयान गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से आए हैं, वह दर्शाता है कि पिछले एक दशक में शिरोमणि अकाली दल के सिमटते जनाधार के बावजूद इस क्षेत्रीय दल को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। अमित शाह ने गठबंधन की घोषणा के बाद कहा कि अकाली दल पंजाब में बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। साथ ही यदि गठबंधन की जीत हुई तो मुख्यमंत्री पद अकाली दल को ही मिलेगा। वैसे यह एक हकीकत है कि इस गठबंधन के बावजूद पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल देना आसान भी नहीं होगा। वैसे आज भी शिरोमणि अकाली दल पर साल 2025 की बेअदबी की घटनाओं और उसके बाद हुए राज्यव्यापी विरोध-प्रदर्शनों का बोझ है। जिसने उस समय अकाली सरकार को हिलाकर रख दिया था। वहीं, केंद्र में सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ तीन कृषि कानूनों को लेकर उपजे गुस्से को पूरी तरह समाप्त नहीं समझ लेना चाहिए। तब किसान काफी नाराज हुए थे और उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर पूरे एक साल तक आंदोलन किया था। अंततः नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। लेकिन इसके बावजूद आगामी चुनावों में भाजपा को कोई सकारात्मक प्रतिसाद पंजाब की जनता की तरफ से नहीं मिला था। तीन माह बाद, 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को सिर्फ दो सीटों में ही संतोष करना पड़ा था। कमोबेश शिअद की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं रही थी। उसे तब सिर्फ तीन ही सीटें मिली थीं। निस्संदेह, यह अकाली दल का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। इसके विपरीत आम आदमी पार्टी ने तब रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। बहरहाल, भाजपा और शिअद के इस पुनर्मिलन से दो मुख्य सवाल खड़े होते हैं। क्या इस गठबंधन के पीछे पंजाब के उन्नयन को लेकर कोई साझा विज़न है? या ये फिर महज चुनावी गणित ही है? सवाल यह भी है कि क्या यह गठबंधन दोनों दलों के लिये लाभदायक साबित होगा? निस्संदेह, आज पंजाब गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसमें आर्थिक दबाव भी एक बड़ा कारण है। राज्य गंभीर बेरोजगारी की चपेट में है। वहीं राज्य में नशीले पदार्थों का बढ़ता कारोबार व सेवन एक गंभीर चुनौती है।

चुनावी महासंग्राम की राह पर उत्तर प्रदेश

(लेखिका- निर्मल रानी)

उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सदस्यों के लिये होने वाले आम चुनाव, फ़रवरी-मार्च 2027 में होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के 4 अन्य राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी संभवतः फ़रवरी-मार्च 2027 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इन सभी पाँचों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च से मई 2027 के बीच समाप्त हो रहा है। इन पांच राज्यों के अलावा, वर्ष 2027 के अंत यानी नवंबर-दिसंबर में दो अन्य राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव निर्धारित हैं। इन विधान सभा चुनावों को 2029 के प्रस्तावित लोकसभा चुनावों के सेमी फ़ाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। वैसे तो इन सभी पांचों राज्यों में चुनाव बेहद दिलचस्प होने की संभावना है परन्तु सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार अपनी चुनावी बिसात बिछाने वाला देश का यह सबसे बड़ा प्रदेश इस बार न केवल साम्प्रदायिक बल्कि जातीय समीकरणों में भी बुरी तरह उलझ चुका है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एस आई आर के बाद, निर्वाचन आयोग ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ड्राफ़्ट मतदाता सूची जारी कर दी है और नाम जोड़ने व सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 17 नवंबर 2026 को जारी ड्राफ़्ट मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश में कुल 13.58 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए हैं। 10 अप्रैल 2026 को एसआईआर के बाद प्रकाशित अंतिम सूची की तुलना में इस मसौदा सूची में 18,84,113 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में महिला मतदाताओं की संख्या में 10,96,828 और पुरुष मतदाताओं की संख्या में 7,87,449 का इज़ाफ़ा हुआ है। इससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 15.44 करोड़ मतदाताओं की जांच के बाद 12.55 करोड़ नाम बरक़रार रखे गए थे और लगभग 2.89 करोड़ नाम सूची से हटाए गए थे। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि पंचायत और विधानसभा मतदाता सूची के भ्रम के कारण 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम सूची में नहीं जुड़ पाए हैं। इसके मद्देनज़र भाजपा ने हर बूथ पर मतदाता जोड़ने के लिए एक महीने का विशेष अभियान शुरू किया है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने भी मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियों और नाम कटने के मुद्दों पर सवाल उठाए हैं और अपने कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची की निगरानी के लिए सक्रिय किया है। उधर मुस्लिम समाज भी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जानबूझ कर पूर्व नियोजित तरीक़े से एक बड़ी साज़िश के तहत मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटे जाने की शिकायत कर रहा है।

उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जहां भाजपा बनाम इण्डिया गठबंधन (कांग्रेस+समाजवादी पार्टी) चुनावी मुक़ाबला होने की संभावना थी वहीँ मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी शुरू से ही अपनी डफ़ली अलग ही बजा रही है। कुछ राजनैतिक विश्लेषक इसे मायावती द्वारा भाजपा को लाभ पहुँचाने की कोशिश की नज़र से भी देख रहे हैं। परन्तु पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी की ए आई एम आई एम ने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से लोकसभा सांसद और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रेशखर की आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) से चुनाव पूर्व समझौता कर उत्तर प्रदेश के राजनैतिक हल्क़ों में खलबली पैदा कर दी है। बसपा जैसे दलों की सक्रियता से मुस्लिम वोटों के बंटवारे की संभावना पर जहां पहले भी चर्चा होती रही है वहीँ चुनाव नज़दीक आने पर बने ओवैसी चंद्रशेखर के यह नये समीकरण व इसके द्वारा उठाये जाने वाले धर्मस्थल विध्वंस,लक्षित एस आई आर,अवैध घुसपैठ, धर्मांतरण, धार्मिक जुलूसों जैसे अनेक ऐतिहासिक विवादों पर तीखे बयान सामाजिक और साम्प्रदायिक संवेदनशीलता को और भी बढ़ा रहे हैं। गोया उत्तर प्रदेश के लगभग 19-20त्न मुस्लिम मतदाताओं के रुझान को लेकर एक ओर जहां सपा-कांग्रेस गठबंधन इस वोट बैंक को एकजुट रखने का प्रयास कर रहे थे वहीं असदुद्दीन ओवैसी के ए आई एम आई एम व चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) और बसपा जैसे दलों की सक्रियता से मुस्लिम वोटों के बंटवारे की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। कुछ राजनैतिक विश्लेषक तो पहले ही असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा के हितसाधक नेता के रूप में देखते आ रहे थे परन्तु अब इस सूची में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भी शामिल हो गया है।

उधर भाजपा समर्थित बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री जोकि पहले भी अपने सम्प्रदायिकपूर्ण व विवादित बयानों के लिये चर्चा में बने रहते हैं उन्होंने पिछले दिनों हमारे राम तुम्हारे कृष्ण जैसी बातें कर और साथ ही भगवान कृष्ण को लेकर अशोभनीय बातें कर समाज में रोष भड़का दिया है। इसके बाद बेशक धीरेन्द्र शास्त्री ने मुआफ़ी मांग ली है परन्तु उनके समर्थन और विरोध को लेकर खिंची रेखायें साफ़ दिखाई दे रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की राजनीति में ब्राह्मण लॉबी और राजपूत/ठाकुर असंतोष जैसे मुद्दे भी चर्चा में हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी के कोर जाटव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सपा, भाजपा और चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी के बीच होड़ देखी जा रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा राम जन्म भूमि आंदोलन का पूरा लाभ उठा लेने के बाद और साथ ही मंदिर के दान व चंदा चोरी जैसे आरोपों में घिरने के बाद अब मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाये जाने के भी चर्चा सुनी जा रही है।

इतना ही नहीं बल्कि अधिकांश दलों द्वारा लगभग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उप-जातियों के आधार पर टिकट वितरण और प्रचार से स्थानीय स्तर पर जातीय वैमनस्य भी बढ़ सकता है। इसके अलावा चुनावों के बीच डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भ्रामक सूचनाओं और भड़काऊ कंटेंट के प्रसार से भी साम्प्रदायिक और जातीय तनाव भड़कने का जोखिम बना रहता है। इसीलिये 2027 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने के कारण इस चुनाव में आक्रामक बयानबाज़ी बढ़ने की पूरी आशंका है।

जबकि एक अध्ययन के मुताबिक़, सभी समुदायों के युवा मतदाता पहचान की राजनीति के साथ-साथ रोज़गार, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार उत्तर प्रदेश, चुनावी महासंग्राम की राह पर जाता दिखाई दे रहा है।

ईश्वर का स्वरूप क्या है?

चिंतन मनन

पहले अपने स्वरूप को जानों

एक महात्मा से किसी ने पूछा- ईश्वर का स्वरूप क्या है?

महात्मा ने उसी से पूछ दिया-तुम अपना स्वरूप जानते हो?

वह बोला- नहीं जानता।

तब महात्मा ने कहा- अपने स्वरूप को जानते नहीं जो साढ़े तीन हाथ के शरीर में मैं-मैं कर रहा है और संपूर्ण विश्व के अधिष्ठान परमात्मा को जानने चले हो। पहले अपने को जान लो, तब परमात्मा को तुरंत जान जाओगे। एक व्यक्ति एक वस्तु को दूरबीन से देख रहा है। यदि उसे यह नहीं ज्ञान है कि वह यंत्र वस्तु का आकार कितना बड़ा करके दिखलाता है, तो उसे वस्तु का आकार कितना बड़ा करके दिखलाता है, तो उसे वस्तु के सही स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा?

अतः अपने यंत्र के विषय में पहले जानना आवश्यक है। हमारा ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा संसार दिखलाता है। हम यह नहीं जानते कि वह दिखाने वाला हमें यह संसार यथावत ही दिखलाता है या घटा-बढ़ाकर या विकृत करके दिखलाता है। गुलाब को नेत्र कहते हैं- यह गुलाबी है।

नासिका कहती है- यह इसमें एक प्रिय सुगंध है। त्वचा कहती है- यह कोमल और शीतल है। चखने पर मालूम पड़ेगा कि इसका स्वाद कैसा है। पूरी बात कोई इंद्री नहीं बतलाती। सब इन्द्रियां मिलकर भी वस्तु के पूरे स्वभाव को नहीं बतला पातीं।



विचार मंथन

सत्ता की राजनीति में धर्म, सनातन और भारतीय संस्कृति पर असर

(लेखक- सनत जैन)

धर्म आस्था, विश्वास और नैतिकता का विषय है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल सत्ता हासिल करने और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए होने लगता है, तो नुकसान केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था का नहीं, बल्कि उस धर्म और संस्कृति का भी होता है, जिसके नाम पर राजनीति की जाती है। भारत में पिछले तीन दशकों से धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति ने इसी तरह की परिस्थितियां पैदा की हैं। आजादी के बाद भारतीय संविधान लागू होने से लेकर 1990 तक भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक परंपराओं, संवैधानिक मूल्यों और कानून के शासन को प्रमुखता देने की कोशिश हुई। हालांकि उस दौर में भी धार्मिक और सामुदायिक विवाद होते रहे, लेकिन 1990 के बाद धर्म को चुनावी राजनीति का प्रभावशाली हथियार बनाने का सिलसिला तेजी से बढ़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि धार्मिक आस्था और राजनीतिक विचारधारा के बीच की दूरी लगातार कम होती चली गई। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि धर्म की रक्षा का दावा करने वाले कुछ लोग, आज धर्म की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं। रामदेव, आसाराम, राम रहीम और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जैसे अलग-अलग पहचान रखने वाले चर्चित बाबाओं के अपराधिक कृत्य ओर समय-समय पर विवाद सामने आते रहे हैं। किसी पर कानूनी आरोप लगे, किसी के बयान विवादों में रहे, किसी की धार्मिक गतिविधियों को लेकर सवाल उठे। ऐसे मामलों ने आम श्रद्धालुओं के मन में यह सवाल पैदा किया है कि धर्म के नाम पर स्थापित होने वाली व्यवस्थाओं का वास्तविक उद्देश्य क्या है? हाल के दिनों में बाबा रामदेव और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बीच सामने आए वैचारिक मतभेदों और बयानों ने इस बहस को और तेज कर दिया है। सवाल यह है कि क्या धार्मिक मंचों पर एक-दूसरे को चुनौती देने, पाखंडी बताने और भगवान राम तथा कृष्ण के नाम का सहारा लेकर अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश से सनातन धर्म मजबूत होगा? भगवान राम और कृष्ण भारतीय संस्कृति के आदर्श हैं। उन्हें किसी बाबा, राजनीतिक दल या चुनावी रणनीति की प्रतिस्पर्धा का माध्यम बनाना करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। धर्म के नाम पर चढ़ावे, दान और मंदिरों की संपत्ति को लेकर उठने वाले विवाद भी कम गंभीर नहीं हैं। मंदिरों में चोरी, धार्मिक संस्थाओं के धन के दुरुपयोग के आरोप और धार्मिक नेतृत्व के बीच संपत्ति तथा प्रभाव को लेकर संघर्ष की खबरें आस्था की बुनियाद को कमजोर करती हैं। जब धर्म के नाम पर लोगों से धन जुटाया जाता है, उसी धन को लेकर धर्म के ठेकेदारों के बीच विवाद पैदा होते हैं। तब श्रद्धालुओं का विश्वास स्वाभाविक रूप से प्रभावित होता है। धर्म-सेवा, त्याग और परोपकार का माध्यम होना चाहिए, न कि आर्थिक लाभ और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का। इस पूरी परिस्थिति का राजनीतिक पक्ष भी समझना जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में हिंदुत्व और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर जो राजनीतिक एकजुटता दिखाई देती थी, उसके भीतर अब वैचारिक और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के संकेत उभर रहे हैं। अलग-अलग धार्मिक संगठनों, बाबाओं और राजनीतिक समर्थकों के बीच बढ़ते मतभेद इस एकजुटता को प्रभावित कर रहे हैं। हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रदर्शन हुए हैं, उसमें जो नई पीढ़ी है उसने धार्मिक प्रतिबद्धता से हटकर जिस तरह अपनी बात रखी है। जिस धार्मिक भावना को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया, वही अब बड़े टकराव का कारण बनती दिखाई दे रही है।

राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कुछ समय के लिए चुनावी लाभ दे सकता है। इसके दीर्घकालीन परिणाम समाज और संस्कृति के लिए नुकसानदायक होते हैं। इतिहास बताता है, धर्म की वास्तविक शक्ति सत्ता के संरक्षण में नहीं, बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों, विश्वास और मानवीय व्यवहार में निहित होती है। आज आवश्यकता इस बात की है, हिंदू समाज बाबाओं के विवादों और राजनीतिक नारों से ऊपर उठकर अपने धर्म के मूल सिद्धांतों को समझे। मंदिरों की संपत्ति की पारदर्शिता सुनिश्चित हो, धार्मिक संस्थाओं की जवाबदेही तय हो। कानून से ऊपर किसी को भी न माना जाए। सनातन धर्म की रक्षा किसी राजनीतिक दल या बाबाओं से नहीं आती है, बल्कि उसकी उदारता, सहिष्णुता, सत्य, सेवा और समरसता की परंपरा से धार्मिक आस्था और संगठन मजबूत होते हैं। सत्ता बदलती रहती है, राजनीतिक समीकरण भी बदलते रहते हैं, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा हजारों वर्षों की विरासत हैं। इन्हें चुनावी लाभ, धार्मिक ध्रुवीकरण और व्यक्तिगत स्वार्थ की भेंट चढ़ाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। धर्म को राजनीति का हथियार बनाने के बजाय राजनीति को धर्म के नैतिक मूल्यों से सीख लेने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से हिंदुओं के बीच में ही बटवारा करने की कोशिश की जा रही है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

क्विक-कॉमर्स डिलीवरी बॉय ने पहले महीने में ही कमाए 39,000, सुनकर सब हैरान

नई दिल्ली।

क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए 10 मिनट में सामान आप तक पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉयज की कमाई को लेकर अक्सर चर्चा होती है। हाल ही में चंडीगढ़ के एक ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर ने अपने पहले महीने की कमाई का खुलासा करके लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पहले महीने में करीब 39,000 रुपए कमाए हैं, जो कि कई पारंपरिक नौकरियों से ज्यादा है। यह डिलीवरी पार्टनर, जिन्होंने अपनी पहचान गोपनीय रखी, उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि पहले महीने की नौकरी का अनुभव काफी अच्छा रहा और उन्हें कोई बड़ी समस्या नहीं आई। आमतौर पर वह सप्ताह के दिनों में करीब 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन सप्ताहांत में ग्राहकों के ऑर्डर बढ़ जाने के कारण उनकी शिफ्ट करीब 16 घंटे तक खिंच जाती है। इस कमाई में डिलीवरी शुल्क के साथ-साथ ग्राहकों से मिलने वाली टिप भी शामिल है। डिलीवरी पार्टनर ने उन लोगों को कुछ अहम सलाह भी दी है, जो डिलीवरी बॉय बनने के बारे में सोच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सुझाव दिया कि यदि आप इस काम में उतरने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीद लें। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ जैसे विकसित और संपन्न शहर में, जहां अच्छी खासी टिप मिलती है, इलेक्ट्रिक बाइक से काम करना काफी आसान हो जाता है और ईंधन का खर्च भी बचता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह काम शारीरिक रूप से काफी थका देने वाला हो सकता है। 12 से 16 घंटे की लंबी शिफ्ट उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं। यह मामला क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स की आय और उनके काम की परिस्थितियों पर नई रोशनी डालता है, साथ ही गिग इकोनॉमी में अवसरों और चुनौतियों को भी दर्शाता है।

कोका-कोला या पेप्सी नहीं आजकल लोग का भा रहा लाहौरी जीरा, मसालों से है भरपूर

पंजाब के तीन चचेरे भाइयों ने खड़ी की कंपनी, 1,112 करोड़ रुपए का रखा लक्ष्य

नई दिल्ली।

आजकल कोल्ड ड्रिंक्स कोका-कोला और पेप्सी की जगह लाहौरी जीरा तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लोग इसे एक स्वस्थ विकल्प के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यह सोडा-आधारित होने के साथ-साथ जीरा और मसालों से भरपूर है, जो पाचन के लिए फायदेमंद है। इस देसी ड्रिंक की बढ़ती मांग ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी है। लाहौरी जीरा की कहानी 2017 में पंजाब के तीन चचेरे भाइयों, सौरभ मुंजाल, निखिल डोडा और सौरभ भूटना की एक साधारण रसोई के प्रयोग से शुरू हुई। निखिल डोडा ने घर पर ही जीरे और मसालों से एक ठंडी, मसालेदार ड्रिंक बनाई, जिसका स्वाद तीनों भाइयों को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे व्यावसायिक रूप देने का फैसला किया। परिवार से शुरुआती आर्थिक मदद मिलने के बाद, उनका यह छोटा सा प्रयोग करीब नौ सालों में एक बड़े ब्रांड में बदल गया। लाहौरी जीरा की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसकी किफायती कीमत भी है, क्योंकि इसकी एक बोतल सिर्फ 10 रुपए की है।

ट्रंप के दबाव में दोबारा सीईओ नहीं बना, बोर्ड ने गहन जांच के बाद लिया फैसला

एनवीडिया के जेन्सेन हुआंग ने वापसी को लेकर चल रही खबरों का किया खंडन

नई दिल्ली।

एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने कंपनी में अपनी वापसी को लेकर चल रही अटकलों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने उन सभी खबरों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में उन्हें दोबारा सीईओ बनाया गया है। जेन्सेन हुआंग ने साफ किया कि कंपनी के बोर्ड ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों की गहन जांच के बाद यह फैसला लिया और उनकी वापसी कंपनी और उसके शेयरधारकों के हित में थी। कर्मचारियों के साथ अपनी पहली बैठक में जेन्सेन हुआंग ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी गलतियों को स्वीकार करते हुए माफी भी मांगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि उनके व्यवहार से उनकी पत्नी लोरी, बच्चों और कंपनी के कर्मचारियों को दुख पहुंचा है। उन्होंने अपनी बेवफाई की बात कबूल की और बताया कि वे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रतिदिन 90 मिनट की थेरेपी ले रहे हैं। हुआंग ने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी पूरी तरह राजनीति से दूर है, हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की एनवीडिया के प्रति प्रशंसा की सराहना की।

शेयर बाजार भारी तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 1502, निफ्टी 470 अंक ऊपर आया

मुम्बई ।

घरेलू शेयर बाजार बुधवार को भारी तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार में ये उछाल दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही बैंकिंग सहित कई क्षेत्रों में खरीददारी हावी रहने से आया है। आज कारोबार के दौरान प्रमुख बेंचमार्क सूचकांकों में बढ़त रही। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1,502 अंक से अधिक उछलकर 83,938.28 अंक पर बंद हुआ, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई का निफ्टी भी लगभग 470 अंकों की तेजी के साथ 25,819.25 अंक पर बंद हुआ। बाजार में इस बढ़त में विदेशी संस्थागत निवेशकों की निरंतर खरीदारी की भी भूमिका रही है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से भी बाजार में उत्साह का माहौल है।

सोमवार को एफआईआई ने 5,672.99 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे, जिससे बाजार धारणा को बल मिला। इसके अतिरिक्त, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड का वायदा भाव 0.19 फीसदी गिरकर 91.38 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जिससे मुद्रास्फीति की चिंताओं में कुछ कमी आई। आज सेंसेक्स की प्रमुख कंपनियों में हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर सबसे अधिक 5.94 फीसदी उछला, जबकि ट्रेंट (3.59 फीसदी), आईसीआईसीआई बैंक (3.44 फीसदी), इंटरग्लोब एविएशन (3.24 फीसदी), एचडीएफसी बैंक (3.18 फीसदी) और बजाज फाइनेंस (3.04 फीसदी) ऊपर आया।



दूसरी ओर टाटा स्टील, भारती एयरटेल और टाइटन के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई के क्षेत्रवार सूचकांकों में एफएमसीजी में सर्वाधिक 3.14 फीसदी की तेजी रही। बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में भी जोरदार खरीदारी देखी गई। वहीं इससे पहले आज सुबह आज सुबह सेंसेक्स 1000.90 अंकों की बढ़त के साथ ही 83,436.89 के स्तर पर खुला। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 308 अंकों के उछाल के साथ ही 25,658.35 के स्तर पर खुला। इस अच्छी शुरुआत से सप्ताह के पहले दिन हुई मुनाफावसूली से बाजार काफी हद तक उबर गया।

सरकारी बैंकों में एसबीआई का जलवा, ग्राहक संख्या में टॉप पर

नई दिल्ली।

भारत में कई निजी बैंकों के बावजूद सरकारी बैंकों पर लोगों का भरोसा आज भी अटूट है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में देश के 12 सरकारी बैंकों में कुल 160.16 करोड़ खाताधारक थे। इन आंकड़ों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित किया है, जो खाताधारकों की संख्या के मामले में शीर्ष पर कायम है। 31 मार्च 2026 तक, एसबीआई के पास 53.03 करोड़ खाताधारक थे। बैंक ने पिछले चार सालों में अपनी ग्राहक संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 46.77 करोड़ से बढ़कर 6.26 करोड़ अधिक हो गई है। यह एसबीआई के व्यापक नेटवर्क और जनता के बीच गहरे विश्वास को दिखाता है। एसबीआई के बाद, बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरे स्थान पर रहा, जिसके पास 18.93 करोड़ खाताधारक हैं।

तीसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है, जिसके 18.53 करोड़ खाताधारक हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा से बहुत पीछे नहीं है। चौथे स्थान पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके पास 16.40 करोड़ ग्राहक हैं। वहीं, केनरा बैंक 11.03 करोड़ खाताधारकों के साथ पांचवें स्थान पर अपनी जगह बनाए हुए है। इन शीर्ष पांच बैंकों के अलावा, बैंक ऑफ इंडिया के भी 11.03 करोड़, इंडियन बैंक के 9.49 करोड़ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 8.25 करोड़ खाताधारक हैं।

बैंक ऑफ इंडिया ने की बीओआई अक्षय डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा

500 दिन के एफडी पर 7.65फसदी तक रिटर्न का मौका, ब्याज दर उम्र और राशि पर निर्भर

नई दिल्ली।

अगर आप अपने निवेश पर आकर्षक रिटर्न पाना चाहते हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) सुनहरा अवसर लाया है। बैंक ने हाल ही में अपनी 500 दिन की विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) योजना बीओआई अक्षय डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस योजना के तहत ग्राहक अब 6.85फीसदी से लेकर 7.65फीसदी सालाना तक ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं, जो ग्राहक की उम्र और जमा की गई रकम पर निर्भर करेगा। बैंक ऑफ इंडिया ने आम ग्राहकों, वरिष्ठ नागरिकों और सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल या उससे ज्यादा के लिए अलग-अलग ब्याज दरें तय की हैं।

आम ग्राहकों को इस योजना पर 6.85फीसदी (कॉलेबल एफडी) और 7.00फीसदी (नॉन-कॉलेबल एफडी) ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये दरें 7.35फीसदी (कॉलेबल एफडी) और 7.50फीसदी (नॉन-कॉलेबल एफडी) हैं। वहीं, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए सबसे ज्यादा ब्याज दरें 7.50फीसदी (कॉलेबल एफडी) और 7.65फीसदी (नॉन-कॉलेबल एफडी) रखी गई हैं। सबसे ज्यादा 7.65फीसदी ब्याज 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के उन बुजुर्गों को मिलेगा, जो एक करोड़ रुपए से ज्यादा और 3 करोड़ रुपए से कम की नॉन-कॉलेबल एफडी कराएंगे। कॉलेबल एफडी में कम से कम



10,000 रुपए जमा किए जा सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए से कम है। नॉन-कॉलेबल एफडी के लिए न्यूनतम जमा राशि एक करोड़ रुपए है।

बैंक ऑफ इंडिया इस एफडी में ब्याज लेने के दो विकल्प भी प्रदान कर रहा है। मंथली पेमेंट या क्वार्टरली पेमेंट। यह सुविधा उन बुजुर्गों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जिन्हें अपनी मासिक या त्रैमासिक जरूरतों के लिए नियमित आय की जरुरी होती है। यह बढ़ोतरी निवेशकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को, बढ़ती ब्याज दरों के माहौल में अपने पैसे पर बेहतर रिटर्न कमाने का एक शानदार मौका दे रही है।

चांदी के भाव में भारी गिरावट-120 डॉलर से फिसलकर 42 डॉलर पर

मुंबई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में इस साल जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, इस उतार-चढ़ाव ने निवेशकों को चिंता में डाल दिया है।

जनवरी 2026 में 120 डॉलर प्रति औंस के अपने ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, अब यह कीमती धातु करीब 42 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है।

इस अप्रत्याशित गिरावट ने बाजार में सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या चांदी की कीमतों में और गिरावट आएगी या यह खरीदारी का एक बेहतर मौका है।

शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के अनुसार, चांदी के लिए 40 डॉलर प्रति औंस का स्तर मजबूत आधार बन सकता है।

उनका सुझाव है कि निवेशक इस स्तर के आसपास एकमुश्त निवेश करने के बजाय धीरे-धीरे किस्तों में खरीदारी करें। इस साल अब तक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब 41 प्रतिशत और घरेलू वायदा बाजार में लगभग 36 प्रतिशत गिर चुकी है, जहां इसका भाव लगभग 1.50 लाख रुपये के आसपास है।

हालांकि, बाजार जानकार अभी और गिरावट की आशंका जता रहे हैं।

उनके अनुमान के मुताबिक, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 8 और 9 दिसंबर को होने वाली बैठक से पहले चांदी 37 से 38 डॉलर प्रति औंस तक फिसल सकती है।

इसके बावजूद, जानकार लंबी अवधि में चांदी के प्रदर्शन को बेहतर मानते हैं और 2027 की दूसरी तिमाही में सोने-चांदी में तेजी देखने की उम्मीद कर रहे हैं। बाजार में मौजूदा अस्थिरता का एक बड़ा कारण वायदा कारोबार में शॉर्ट पोजीशन का बढ़ना और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) से पूंजी का बाहर निकलना है। दूसरी ओर, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगों से चांदी की औद्योगिक मांग बनी हुई है। आने वाले दिनों में अमेरिकी महंगाई, रोजगार और विनिर्माण गतिविधियों से जुड़े आंकड़े, साथ ही फेडरल रिजर्व का फैसला, चांदी की कीमतों की अगली दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

2027 तक सोने का अंतर्राष्ट्रीय भाव 4,650 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस तक पहुंच सकता है

गोल्डमैन सैक्स ने सोने की इस संभावित तेजी के पीछे तीन प्रमुख वजहें बताई

नई दिल्ली।

प्रमुख वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने सोने की कीमतों को लेकर एक बड़ा अनुमान जताया है। बैंक का मानना है कि वर्ष 2027 के आखिर तक सोने का अंतर्राष्ट्रीय भाव 4,650 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस तक पहुंच सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने सोने की इस संभावित तेजी के पीछे तीन प्रमुख वजहें बताई हैं, जिनमें सेंट्रल बैंकों की बढ़ती खरीदारी, चीन द्वारा अपने सोने के भंडार में हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना और भविष्य में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना शामिल है। मीडिया रिपोर्ट में बैंक के मुताबिक दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जिसका एक बड़ा कारण रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज किया जाना रहा है। इस घटना के बाद कई देशों ने अपने रिजर्व में सोने को ज्यादा महत्व देना शुरू किया है।

गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2028 तक सेंट्रल बैंक हर महीने औसतन 60 टन सोना खरीद सकते हैं, जबकि 2022 से पहले यह औसत मात्र 17 टन प्रति माह था।दूसरी वजह चीन की बढ़ती मांग है। चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी है और उसके कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी करीब 11.8 फीसदी है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि चीन भविष्य में इसे बढ़ाकर 20 फीसदी तक कर सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग और मजबूत होगी। तीसरी प्रमुख वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले हैं।

घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट

नई दिल्ली ।

घरेलू बाजार के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। इससे खरीदारों और निवेशकों ने अब सतर्क रुख अपना लिया है और वह अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं।

इसी कारण घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएस) पर सोने की कीमतें 533 रुपये रुपये कम होकर 1,21,796 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गयी हैं। इसके साथ ही चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट रही। ये 738 रुपये गिरकर 1,44,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में 0.43 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह 3,547 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं, चांदी भी 0.42 डॉलर कमजोर होकर 40.61 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। ववहीं भारतीय बाजारों की बात करें तो 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतों में हल्का अंतर आया है। पुणे, वडोदरा, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत 12,781 रुपये प्रति ग्राम बनी हुई है जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह 12,791 रुपये प्रति ग्राम पर है।

पेट्रोल में एथेनॉल जांच पर पेंच-केरल में तेल कंपनियों ने शुद्ध सैंपल देने से किया इंकार

तिरुवंतनमपुरम।

केरल में पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को लेकर चल रही जांच में बड़ी बाधा आ गई है। राज्य सरकार की शिकायत के बाद शुरू हुई प्रक्रिया में अब तेल कंपनियों के असहयोग के कारण गतिरोध पैदा हो गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने 24 नवंबर को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी को पत्र लिखकर मामले में केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। राज्य सरकार का आरोप है कि तेल कंपनियां पेट्रोल में निर्धारित मात्रा से अधिक एथेनॉल मिला रही हैं, जिससे वाहनों के इंजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसकारण केरल सरकार ने राज्य भर के पेट्रोल पंपों से नमूने एकत्र कर एक गहन जांच शुरू की थी। हालांकि, जब इन नमूनों को सरकारी केमिकल लैब में भेजा गया, तब लैब ने शुद्ध, एथेनॉल-मुक्त पेट्रोल के नमूनों के बिना मौजूदा पेट्रोल में एथेनॉल की सटीक मात्रा का पता लगाने में असमर्थता जाहिर की है। केरल की कांग्रेस सरकार में मंत्री जैकब ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी प्रमुख तेल कंपनियां शुद्ध पेट्रोल के सैंपल उपलब्ध करने से इंकार कर रही हैं। इन शुद्ध सैंपलों की आवश्यकता इसलिए है ताकि प्रयोगशाला में मौजूदा नमूनों के साथ उनकी तुलना करके एथेनॉल की वास्तविक मात्रा का सटीक विश्लेषण किया जा सके। मंत्री जैकब ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसी तेल कंपनी की छवि खराब करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण ईंधन मिले और पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा तय सीमा के भीतर हो।

जिम में सप्लीमेंट बेचा तो होगी सख्त कार्रवाई, एफएसएसएआई लाइसेंस लेना अनिवार्य

एफडीए अब जिम में स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स की अनाधिकृत बिक्री को लेकर सख्त

नई दिल्ली।

महाराष्ट्र का खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) अब जिम में स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स की अनाधिकृत बिक्री पर कड़ी नकेल कसने जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से लगातार छापेमारी और कार्रवाई कर रहे एफडीए ने अब जिम मालिकों पर भी निशाना साधा है।

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने ऐलान की है कि जिम में सप्लीमेंट बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) लाइसेंस होना अनिवार्य होगा। तुकाराम मुंढे ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जिम में बेचे जाने वाले प्रोटीन पाउडर या अन्य हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर किए गए स्वास्थ्य संबंधी दावों को लेकर एफडीए सख्त है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने स्पष्ट किया कि थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और जिम संचालक अपनी जिम्मेदारी उत्पाद बनाने वालों पर नहीं डाल सकते। उन्हें खुद यह तय करना होगा कि जो उत्पाद वे बेच रहे हैं, वे असली हों, उनमें कोई झूठा दावा न किया गया हो, और उनके पास (एफएसएसएआई का उचित लाइसेंस हो। तुकाराम मुंढे ने यह भी साफ किया कि किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी, निर्माता या उत्पादक को स्वास्थ्य संबंधी विशेष लाभों का दावा करने या प्रोडक्ट्स के लेबल पर ऐसे दावे छापने की अनुमति नहीं है।

ऐसे दावे पूरी तरह भ्रामक और गैरकानूनी माने जाएंगे। जिम संचालकों को चेतावनी दी गई है कि यदि वे अपने परिसर में सप्लीमेंट बेचना चाहते हैं, तो उन्हें अनिवार्य रूप से एफएसएसएआई लाइसेंस हासिल करना होगा। बिना अनुमति के ऐसे उत्पादों की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला जिम जाने वाले लोगों की सुरक्षा और उन्हें गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

एफएनपीओ ने की कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े नियमों में बदलाव की मांग

संगठन ने कहा-मौजूदा नियमों में विसंगतियां, 10 से 12 करना पड़ता है इंतजार

नई दिल्ली।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (एफएनपीओ) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े नियमों में बदलाव की मांग की है। संगठन का कहना है कि मौजूदा नियमों में विसंगतियां हैं, जिसके कारण कुछ पदों पर कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए 10 से 12 साल तक इंतजार करना पड़ता है, जबकि अन्य पदों पर यह अवधि काफी कम होती है। एफएनपीओ ने 20 नवंबर 2026 को 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की मांग की।

संगठन ने सुझाव दिया है कि पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि एक साल और अधिकतम चार साल तय की जाए।

हालांकि, यह अवधि कर्मचारियों के काम की प्रकृति, उनकी जिम्मेदारी और संबंधित विभाग की जरूरतों के हिसाब से तय होनी चाहिए।

संगठन ने इस बदलाव की जरुरत इसलिए बताई है क्योंकि विभिन्न विभागों में पदोन्नति के नियमों में भारी अंतर देखा जाता है।

उदाहरण के लिए वर्तमान में लेवल 2 से लेवल 4 पर पदोन्नति के लिए 8 साल की सेवा अनिवार्य है, जबकि लेवल 4 से लेवल 6 पर जाने के लिए 10 साल और लेवल 6 से लेवल 10 पर पदोन्नति के लिए भी 10 साल का इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह, कुछ अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए 12 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है, जबकि कुछ अन्य पदों पर केवल 1 से 3 साल की सेवा के बाद भी पदोन्नति मिल जाती है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यह असमानता कर्मचारियों के करियर को प्रभावित करती है और उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है।

देश के तीन बड़े बैंक डूबे तो देश की वित्तीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था हिल जाएगी

आरबीआई ने एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को डी-सिब स का दिया तमगा

नई दिल्ली।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को देश के सबसे बड़े बैंकों यानी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट जारी कर दी है। ये वह बैंक हैं यदि इनमें से किसी एक पर भी संकट आया या यह डूबा, तो पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था बुरी तरह बिगड़ सकती है। आरबीआई ने वर्ष 2026 के लिए भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को डी-सिब स बैंक का तमगा दिया है। ये तीनों बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम हैं इन्हें 'टू बिग टू फेल' यानी इतने बड़े कि डूब नहीं सकते माना गया है।

डी-सिब फ्रेमवर्क के तहत भारतीय रिजर्व बैंक देश के उन बैंकों की पहचान करता है, जिनका आकार, कारोबार और बैंकिंग सिस्टम में दखल इतना बड़ा है कि उनके विफल होने से पूरी अर्थव्यवस्था पर संकट आ सकता है। ऐसे बैंकों को सुरक्षित रखने के लिए आरबीआई उन पर सामान्य बैंकों के मुकाबले ज्यादा सख्त निगरानी रखता है। केंद्रीय बैंक ने 22 जुलाई 2014 को यह फ्रेमवर्क लागू किया था। इस सूची में सबसे पहले 2015 में एसबीआई को शामिल किया गया था। 2016 में आईसीआईसीआई बैंक और 2017 में एचडीएफसी बैंक को डी-सिब बैंक का दर्जा मिला।इन तीनों बैंकों को किसी भी आपातकालीन आर्थिक संकट या नुकसान से बचाने के लिए आरबीआई ने इनके लिए कैपिटल कंजर्वेशन बफर के अलावा कुछ अतिरिक्त पूंजी अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य किया है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

जहां कभी तबाही मचाई थी चट्टानों ने वहीं आज उभरी आस्था, जानें 31 दिव्य आकृतियों का रहस्य



2013 में केदारनाथ घाटी पर आई भीषण त्रासदी ने पूरे देश को हिला दिया था। उस दौरान पहाड़ टूटे, विशाल चट्टानें बहकर मंदिर के पास आकर रुक गईं और हजारों लोगों की जान बचाने में ढाल बनीं। आज वही चट्टानें एक नए आस्था केंद्र के रूप में लोगों का ध्यान खींच रही हैं।

चट्टानों पर दिखीं 31 रहस्यमयी आकृतियां

स्थानीय लोगों, पुजारियों और कई विशेषज्ञों के अनुसार, इन चट्टानों की सतह पर करीब 31 अलग-अलग आकृतियां उभरकर दिखाई दे रही हैं। इनमें भगवान शिव से मिलती-जुलती आकृतियां, नंदी के जैसे आकार, साधु-संतों की आकृतियों जैसी रेखाएं भक्तों के रूप में दिखने वाली उभरी रूप-रेखाएं दूर से ये आकृतियां साधारण सा पत्थर ही लगती हैं, लेकिन पास जाकर देखने पर इनके आकार बेहद स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस वजह से कई लोग इन्हें प्राकृतिक मूर्ति परिसर जैसा मानने लगे हैं।

क्या यह प्रकृति का चमत्कार या दिव्य संकेत?

अब तक वैज्ञानिक रूप से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ऐसी विशाल और गहरी आकृतियां चट्टानों पर कैसे बनीं। कुछ विशेषज्ञ इन्हें प्राकृतिक भू-आकृतिक संरचना बताते हैं, जबकि कई श्रद्धालु इसे शिव की उपस्थिति और दिव्य संकेत मान रहे हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है- '2013 की आपदा के बाद भी मंदिर सुरक्षित रहा... अब इन चट्टानों में शिव के रूप दिखना कोई साधारण बात नहीं है।'

तीर्थयात्रियों के लिए नया आकर्षण

इन चट्टानों को देखने के लिए अब केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। लोग इन्हें आस्था का प्रतीक, चमत्कार का संकेत, प्रकृति की अद्भुत कला और शिव की कृपा मानकर प्रति दिन बड़ी संख्या में दर्शन करने आ रहे हैं।

रहस्य और श्रद्धा बढ़ाती अनोखी कहानी

चाहे ये आकृतियां संयोग हों या प्रकृति के अद्भुत खेल— केदारनाथ की ये चट्टानें अब एक नई आध्यात्मिक कहानी बन चुकी हैं। 2013 की त्रासदी के दौरान मंदिर को बचाने वाली ये चट्टानें आज श्रद्धालुओं की आस्था का नया केंद्र बनकर उभर रही हैं। यह घटना बताती है कि प्रकृति और आस्था जब मिलती हैं, तो इतिहास खुद-ब-खुद नई कहानी रच देता है।





बादलों का घर मेघालय : इन 5 जगहों की सैर आपको जीवन भर याद रहेगी, बनाएं ट्रिप का प्लान!

नॉर्थ-ईस्ट राज्य प्राकृति और सुंदर वादियों के लिए जाना जाता है। अगर आप मेघालय जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है। मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। यहां की सुंदरता दुनियाभर में फेमस है। मेघायलय में पानी भी शीशे की तरह चमकता है और घने जंगल की सुंदरता देखकर आप कहीं न कहीं खो जाएंगे। जो एक बार मेघालय घूमने जाएगा वो वही का होकर रह गया है। मेघालय में आपको पहाड़, झरने, नदियां, झील, हरे जंगल सबकुछ देखने को मिलेगा। आइए आपको बताते हैं आप किन जगहों पर जरुर घूमने जाएं।

शिलॉन्ग

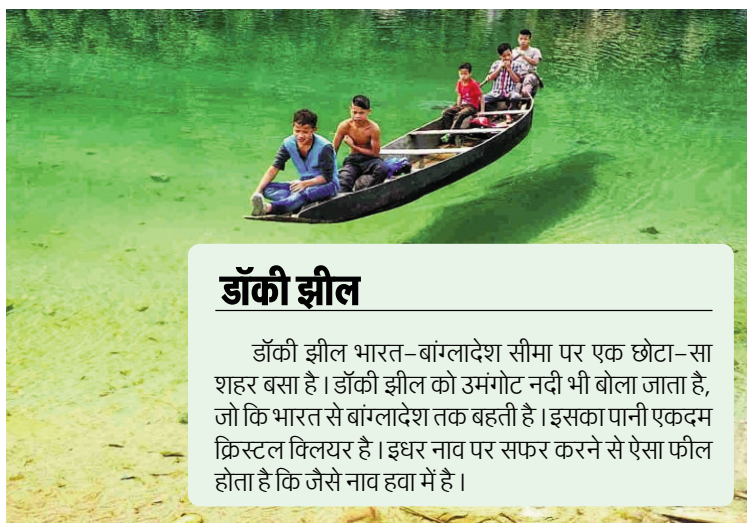

डॉकी झील

डॉकी झील भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक छोटा-सा शहर बसा है। डॉकी झील को उमंगोट नदी भी बोला जाता है, जो कि भारत से बांग्लादेश तक बहती है। इसका पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इधर नाव पर सफर करने से ऐसा फील होता है कि जैसे नाव हवा में है।

मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग घूमने जरुर जाएं। यह शहर बेहद ही खूबसूरत और हरियाली से घिरा हुआ है। मेघालय पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ है शिलॉन्ग। इसे मिनी स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। शिलॉन्ग में आप व्यू पॉइंट, लैत्कोर पीक, स्प्रेअद ईगल फॉल्स, लेडी ह्यदारी पार्क और एलिफेंट फॉल्स को जरुर देखें।

दावकी

अगर आप मेघालय जा रहे हैं, तो पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में स्थित दावकी छोटा सा टाउन है, यहां पर घूमने के लिए कई सारी जगहें हैं। इधर आपको सुंदर झरने देखने को मिलेंगे। दावकी में जाफलोंग जोरी पॉइंट, बुरहिल झरने, मावल्यान्नॉग, रिवाई जैसी खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकती हैं।

मौसिनराम

मेघालय के खासी हिल्स में मौसिनराम एक सुंदर बस्ती है, यह अपनी प्राकृतिक स्टैलेग्माइट शिवलिंग जैसी संरचनाओं के लिए जाना जाता है। यहां पर मावजिम्बुइन गुफा देखने को लायक मिलती है। इस गुफा में शिवलिंग भी रखी है, जो कि स्टैलेग्माइट के लिए जानी जाती है। यहां का वातावरण एकदम शांत और सुकून से भरा हुआ है। कलकल करता हुआ पानी की आवाज आपके मन को शांति प्रदान करेगा।

मावफलांग पवित्र वन

मेघालय में मावफलांग वन एक प्रचीन जंगल है, जो काफी शुद्ध व पवित्र माना जाता है। इस जंगल से एक भी पत्ती बाहर लेकर जाना माना है और इस जंगल में आपको रुद्राक्ष के पेड़ मिलेंगे, हर मुख वाली रुद्राक्ष पेड़ में लगी होती है।

खूबसूरती और रोमांच का अनोखा संगम, हिमाचल का 'कौमिक' गांव, जहां चांदनी रातें बिखेरती हैं जादू

उत्तराखंड में ऐसी कई अद्भुत और शानदार जगहें मौजूद हैं, जहां पर घूमने के लिए हर मौसम में विश्व के हर कोने से पर्यटक पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौमिक एक ऐसा गांव है, जिसकी खूबसूरती देखकर हर कोई अद्भुत ख्वाबों की दुनिया में चला जाएगा।

हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमाचल के हृदय में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसको उत्तराखंड की तरह ही 'देव भूमि' के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जो 'बर्फीले पहाड़ों के प्रांत' के नाम से फेमस है। उत्तराखंड में ऐसी कई अद्भुत और शानदार जगहें मौजूद हैं, जहां पर घूमने के लिए हर मौसम में विश्व के हर कोने से पर्यटक पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौमिक एक ऐसा गांव है, जिसकी खूबसूरती देखकर हर कोई अद्भुत ख्वाबों की दुनिया में चला जाएगा। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कौमिक की खासियत और इसके आसपास कुछ अद्भुत जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

कौमिक गांव

कौमिक गांव को कई लोग कोमिक के नाम से भी जानते हैं। यह गांव खूबसूरत और मनमोहक गांव हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है।

कौमिक गांव हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 444 किमी दूर है। इसके साथ ही कौमिक गांव मनाली से 202, कुल्लू से 224 और रिकांग पिओ से करीब 228 किमी दूर है।

कौमिक गांव की खासियत

हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले की स्पीति में स्थित कौमिक गांव काफी ज्यादा खूबसूरत है। कौमिक गांव को भारत के अलावा दुनिया के सबसे गांव होने की ख्याति भी प्राप्ति होती है।

कौमिक गांव समुद्र तल से करीब 15 हजार फीट की ऊंचाई पर मौजूद कौमिक गांव ढके-ढके ऊंचे पहाड़, क्रिस्टल से अधिक साफ झील-झरनों का पानी और नीले आसमान के लिए जाना जाता है। कौमिक गांव की चांदनी रात पर्यटकों को

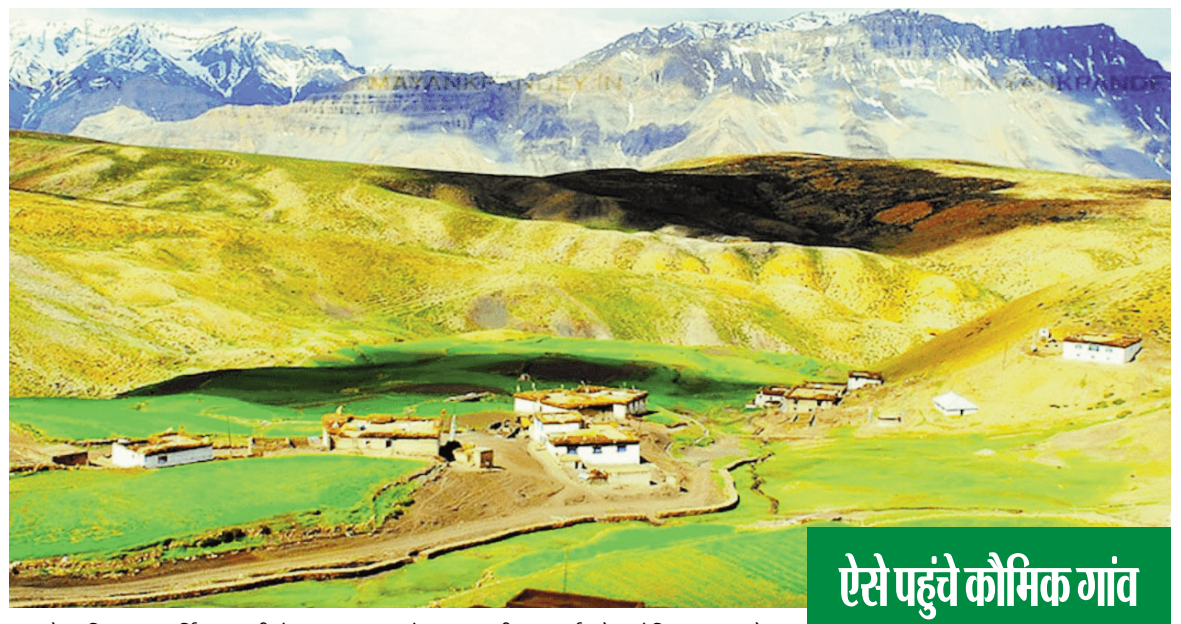

सबसे अधिक आकर्षित करती है। यहां का शांत और शुद्ध वातावरण भी पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। इसलिए इस गांव को हिमाचल प्रदेश का हसीन जन्नत माना जाता है।

लुंडुप त्सेमो गोम्पा बौद्ध मठ

कौमिक गांव अपनी खूबसूरती के अलावा लुंडुप त्सेमो गोम्पा बौद्ध मठ के लिए भी आकर्षण का केंद्र माना जाता है। इस मठ के बारे में बताया जाता है कि इसका इतिहास करीब 500 साल से भी अधिक पुराना है।

पहाड़ी की चोटी पर मौजूद होने के कारण लुंडुप त्सेमो गोम्पा बौद्ध मठ को एक्सप्लोर करना बहुत लोगों का सपना होता है। मठ की ऊंचाई से कौमिक गांव के आसपास के लुभावने और हसीन दृश्यों को आंखों में कैद कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर यादगार फोटोग्राफी भी कर सकते हैं।

एडवेंचर प्रमियों के लिए स्वर्ग

यह गांव सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि गोम्पा बौद्ध मठ और एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग माना जाता है। यह गांव विश्व भर में सबसे ऊंचे ट्रैकिंग और हाईकिंग के लिए फेमस है।

सर्दियों के मौसम के अलावा आप यहां पर गर्मियों में भी आ सकते हैं। यहां पर हजारों लोग ट्रैकिंग, बाइक राइड और कैंपिंग के लिए भी आते हैं। आप यहां पर रॉक क्लाइंब का भी लुत्फ उठा सकते हैं।

ऐसे पहुंचे कौमिक गांव

बता दें कि इस गांव पहुंचना बेहद आसान है। इसके लिए आप दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से बस लेकर स्पीति वैली पहुंच सकते हैं। दिल्ली कश्मीरी गेट से स्पीति वैली के लिए बस चलती हैं। स्पीति वैली पहुंचने के बाद आप बाइक रेंट पर लेकर कौमिक गांव पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप शिमला से भी बस लेकर कौमिक गांव पहुंच सकते हैं।

ये कैसा झरना जो बहता है उल्टा! नीचे गिरने की बजाए ऊपर चढ़ता है पानी, देखकर हिल जाएगा दिमाग

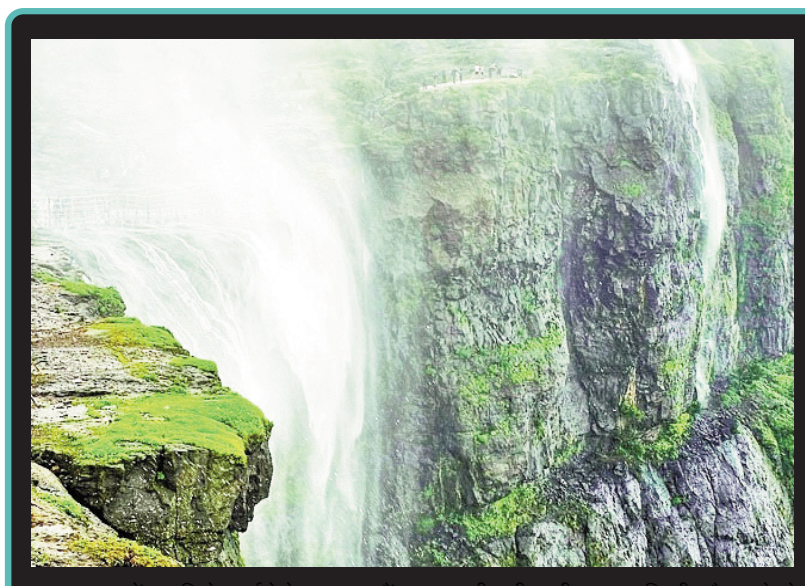

भारत में प्रकृति के कई ऐसे चमत्कार हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इन्हीं में से एक है महाराष्ट्र का नानेघाट वाटरफॉल, जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देता है। आमतौर पर झरने ऊपर से नीचे गिरते हैं, लेकिन यह झरना नीचे से ऊपर बहता दिखाई देता है। इस अनोखे नजारे को देखने के लिए हर साल भारी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं।

कहां स्थित है यह अनोखा झरना?

यह अनोखा झरना नानेघाट वाटरफॉल के नाम से मशहूर है और कोंकण समुद्र तट तथा जुन्नार नगर के बीच स्थित है। मुंबई से इसकी दूरी करीब 120 किमी और पुणे से लगभग 150 किमी है। नाना घाट और 'रिवर्स वाटरफॉल' के नाम से जाना जाने वाला यह स्थान अपने अनोखे प्राकृतिक दृश्य के कारण पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है।

क्यों बहता है यह झरना उल्टी दिशा में?

गुरुत्वाकर्षण के नियम के मुताबिक हर चीज ऊपर से नीचे की ओर आती है, लेकिन नानेघाट का यह झरना तेज हवाओं के कारण ठीक उल्टा व्यवहार करता है। यहां हवा इतनी तेज़ चलती है कि नीचे गिरता पानी हवा का दबाव पकड़कर ऊपर उड़ने लगता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इसी तेज हवा की दिशा और गति के कारण यह झरना उल्टी दिशा में बहता दिखाई देता है, जो इसे बेहद रहस्यमयी और अनोखा बनाता है।

इसे देखने पर क्या महसूस होता है?

जो भी इस झरने को पहली बार देखता है, वह दंग रह जाता है। दूर से ऐसा लगता हे मानो पानी ऊंची पहाड़ी की तरफ ऊपर चढ़ रहा हो। यह अद्भुत नज़ारा लोगों को कुछ पल के लिए स्तब्ध कर देता है, क्योंकि प्रकृति का ऐसा उल्टा करिश्मा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता।

कैसे पहुंचे नानेघाट रिवर्स वाटरफॉल?

अगर आप नानेघाट रिवर्स वाटरफॉल देखने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां पहुंचना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको कल्याण बस स्टैंड जाना होगा, जहां से जुन्?नार और नानेघाट के लिए नियमित बसें मिल जाती हैं। चाहें तो आप सड़क मार्ग से भी अपनी कार या टैक्सी से आराम से नानेघाट पहुंच सकते हैं। यहां तक पहुंचने का रास्ता सुंदर घाटों और हरियाली से भरा है, जो यात्रा को और भी खास बनाता है।

ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग

नानेघाट ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह ट्रेल घाटघर के घने जंगल क्षेत्र का हिस्सा है और रोमांच से भरपूर प्राकृतिक रास्तों से होकर गुजरता है। कल्याण-अहमदनगर हाईवे से शुरू होने वाला यह ट्रेकिंग रूट साहसिक यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि यहां का शांत वातावरण, पहाड़ी दृश्य और ठंडी हवाएं पूरे सफर को यादगार बना देती हैं।

घूमने का सबसे अच्छा समय

नानेघाट रिवर्स वाटरफॉल को देखने का सबसे अच्छा समय मानसून का मौसम माना जाता है। जुलाई से सितंबर के बीच यहां की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। इस दौरान हवाएं बेहद तेज चलती हैं, जिसकी वजह से झरना सबसे मनमोहक तरीके से उल्टी दिशा में बहता दिखाई देता है। यही समय इस अनोखे प्राकृतिक चमत्कार को नजदीक से देखने के लिए परफेक्ट माना जाता है।



Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

चीन में अधिकारी को मौत की सजा: पहले दोस्ती, फिर धमकी; विदेशी खुफिया एजेंट ने जासूसी के लिए कैसे फंसाया

बीजिंग, एजेंसी। चीन में एक अधिकारी को किसी दूसरे देश के लिए जासूसी करने के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। उसने देश के गोपनीय दस्तावेज और जानकारी विदेशी खुफिया एजेंसी को दी थी। सरकारी संस्था से जुड़ी एक प्रकाशन कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। गोल्ड वॉल प्रेस नाम की इस कंपनी का संबंध चीन के राष्ट्रीय गोपनीयता संरक्षण प्रशासन से है। कंपनी ने बताया कि दोषी अधिकारी का उपनाम मा था। वह विदेश में काम कर रहा था। इसी दौरान एक विदेशी खुफिया एजेंसी ने उससे संपर्क किया। एजेंसी ने उसे अपने लिए काम करने के लिए तैयार किया। चीन की अदालतें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी आमतौर पर सार्वजनिक नहीं करतीं। लेकिन अब ऐसे मामले सामने आने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों से चीन का राज्य सुरक्षा मंत्रालय और गोल्ड वॉल प्रेस ऐसे मामलों की जानकारी ज्यादा देने लगे हैं। ये संस्थाएं गिरफ्तारी की जानकारी देती हैं। साथ ही, सोशल मीडिया, फिल्म और कॉमिक्स के जरिये भी लोगों को जासूसी के खतरे के बारे में चेतावनी देती हैं।

शेख हसीना 16 दिसंबर को लौटेंगी बांग्लादेश

ढाका,एजेंसी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 16 दिसंबर को अपने देश लौटने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय विमानन कंपनी बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस से दिल्ली से उड़ान की मांग की है। उनकी प्रस्तावित वापसी मृत्युदंड, प्रत्यर्पण अनुरोध और बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच हो रही है। यह पहली बार है जब उन्होंने अपनी वापसी की तारीख तय की है। बांग्लादेश में राजनीतिक और कानूनी तनाव लगातार बढ़ रहा है। 16 दिसंबर बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 1971 में पाकिस्तान से देश की मुक्ति का प्रतीक है। हसीना के प्रवक्ता सैयद मोजम्मेल अली के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री इस अवसर पर ढाका लौटना चाहती हैं। हसीना 15 साल के शासन को समाप्त करने वाले छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद देश छोड़कर भागी थीं। वह दो साल से अधिक समय पहले भारत में निर्वासन में चली गई थीं। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से दिल्ली से उनके परिवहन की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। उनका तर्क है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनकी वापसी में सहायता करे। यह घोषणा हसीना द्वारा नए बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) मांगने के हफ्तों बाद आई है। उन्होंने अपनी वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए ये दस्तावेज मांगे थे। अगस्त 2024 में भारत भागने के बाद उनके मौजूदा दस्तावेज रद कर दिए गए थे। उनके कानूनी प्रतिनिधियों, लंदन स्थित मैट्रिक्स चैंबर्स ने 9 नवंबर को बांग्लादेश हाई कमीशन से संपर्क किया। उन्होंने नई दिल्ली में दस्तावेज के जारी करने की मांग की थी।

स्टॉर्मी डेनियल्स हश मनी केस: ट्रंप को सजा रद्द कराने का नया रास्ता मिला

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में अपनी आपराधिक सजा रद्द कराने की दिशा में नया कानूनी रास्ता मिल गया है। संघीय अपील अदालत ने सोमवार को मामले को न्यूयॉर्क की राज्य अदालत से संघीय अदालत में स्थानांतरित करने का रास्ता खोल दिया। इससे ट्रंप को राष्ट्रपति पद से जुड़ी कानूनी छूट का आधार लेकर अपनी दोषसिद्धि रद्द कराने की मांग करने का मौका मिल सकता है। दूसरी अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रंप के मामले को राज्य अदालत में ही रखने का निर्णय दिया गया था। इसी अदालत में ट्रंप पर 34 गंभीर आपराधिक आरोपों में मुकदमा चला था और उन्हें दोषी ठहराया गया था। मामला वयस्क फिल्मों की अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल्स को दिए गए 1.30 लाख डॉलर के भुगतान को छिपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में हेराफेरी से जुड़ा है।

निचली अदालत को जल्द फैसला देने का निर्देश

अपील अदालत ने निचली अदालत को जल्द फैसला करने का निर्देश दिया है कि मामले को संघीय अदालत में रखा जाना चाहिए या नहीं। यदि मामला संघीय अदालत में जाता है, तो ट्रंप यह दलील दे सकते हैं कि राष्ट्रपति पद से जुड़े कार्यों के लिए मिली कानूनी छूट के आधार पर उनकी दोषसिद्धि रद्द की जाए। इस फैसले के बाद न्यूयॉर्क की राज्य अदालत में ट्रंप की ओर से दायर समानांतर अपील की कार्यवाही भी रुक गई है। ट्रंप ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

जंग का खामियाजा सभी देश बराबर नहीं भुगतते, भारत ने याद दिलाया 1943 का बंगाल अकाल

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में 1943 के बंगाल के अकाल का जिक्र किया। भारत ने बताया कि दुनिया में होने वाली जंगों का असर सभी देशों पर एक जैसा नहीं पड़ता। विकासशील देशों को इसकी सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। भारत ने यूक्रेन युद्ध के कारण खाद्य संकट रोकने के लिए कदम उठाने की मांग भी की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने सोमवार को सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में यह बात कही। सुरक्षा परिषद की बैठक का विषय था- ऊर्जा के अहम ढांचे और वैश्विक खाद्य आपूर्ति के लिए काला सागर के समुद्री रास्तों की सुरक्षा। पर्वतनेनी ने कहा, दुनिया में होने वाले संघर्षों के कारण कई देशों में भोजन, ईंधन, खाद और ऊर्जा की कमी हो रही है। इसका सबसे ज्यादा असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि युद्ध की कीमत सभी देश बराबर नहीं चुकाते। उन्होंने आगे कहा, आज के वैश्विक संघर्षों के कारण पैदा हुए भोजन, ईंधन और खाद संकट से वैश्विक दक्षिण के देश सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

बंगाल में अकाल का जिक्र क्यों किया : हरीश पर्वतनेनी ने 1943 के बंगाल अकाल का भी जिक्र किया। इस अकाल में 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।



उन्होंने कहा, यह अकाल आज भी युद्ध के खौफनाक मानवीय नुकसान की याद दिलाता है। दूर किसी दूसरे देश में जारी युद्ध का असर भी आम लोगों पर पड़ सकता है। युद्ध के दौरान बिना रोक-टोक लिए गए फैसले और प्राथमिकताएं इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं।

उन्होंने कहा, दुनिया के सभी देश एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में यूक्रेन युद्ध का असर हर जगह महसूस किया जा रहा है। यह युद्ध अब पांचवें साल में पहुंच चुका है।

भारत ने युद्ध खत्म करने के लिए क्या कहा : राजदूत पर्वतनेनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को भी याद किया। उन्होंने कहा, दुनिया को लगातार चलने वाले युद्धों से आगे बढ़कर युद्ध खत्म करने की दिशा में जाना होगा। उन्होंने दोहराया कि भारत इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के सभी प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ मजबूती से खड़े हैं। मोदी ने साफ कहा है कि यह युग युद्ध का नहीं है।

युद्ध से खाद्य संकट कैसे बढ़ता है : भारत ने चिंता जताई कि जंग के कारण खाद्य संकट और बढ़ जाता है। इससे खेती प्रभावित होती है। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर होते हैं। जरूरी ढांचे को नुकसान पहुंचता है। राहत पहुंचाने में भी मुश्किलें आती हैं। जंग का असर केवल संघर्ष वाले इलाकों तक सीमित नहीं रहता। इससे ऊर्जा, खाद, परिवहन और कृषि व्यापार की आपूर्ति भी प्रभावित होती है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान वैश्विक दक्षिण के देशों को होता है। पर्वतनेनी ने कहा, वैश्विक दक्षिण के लिए शांति कोई काल्पनिक बात नहीं है। यह तब हासिल होती है, जब भूखे लोगों को खाना मिलता है, जब कोई जहाज बंदरगाह तक पहुंचता है और जब कोई नाविक सुरक्षित अपने घर लौटता है। भारत ने सुरक्षा परिषद से अपील की कि वह कुछ बातों को प्राथमिकता दे। इनमें मानवीय सहायता पहुंचाना, आम लोगों के जरूरी ढांचे की सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर आवाजाही की आजादी शामिल है। भारत ने कहा, राहत सामग्री की आपूर्ति और वैध व्यापार में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। पर्वतनेनी ने कहा, भारत के लिए बातचीत और कूटनीति, सुरक्षित व्यापारिक जहाजरानी और अनाज तथा ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति व्यावहारिक जरूरतें हैं।

दूसरे विश्व युद्ध और बंगाल अकाल का जिक्र क्यों किया : पर्वतनेनी ने कहा, मौजूदा हालात दूसरे विश्व युद्ध के समय जैसे ही हैं। उस समय भी युद्ध शुरू करने के लिए जिम्मेदार नहीं रहे लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने कहा, यह मौजूदा स्थिति दूसरे विश्व युद्ध के समय से अलग नहीं है। उस समय भी संघर्ष शुरू करने के लिए जिम्मेदार नहीं रहे लोगों को अनजाने में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। उन्होंने 1943 के बंगाल अकाल का फिर जिक्र किया।

उन्होंने कहा, भारत में 1943 के विनाशकारी बंगाल अकाल के कारण हुई पीड़ा और तकलीफ दूर किसी संघर्ष के कारण होने वाले खौफनाक मानवीय नुकसान की स्पष्ट याद दिलाती है, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। यह नुकसान युद्ध के दौरान बिना रोक-टोक लिए गए फैसलों और प्राथमिकताओं के कारण हुआ। उन्होंने कहा, इन्हीं गंभीर नतीजों के कारण भारत खाद्य असुरक्षा को रोकने को इतनी अहमियत देता है।

वैश्विक खाद्य आपूर्ति में काला सागर कितना अहम है : पर्वतनेनी ने कहा, काला सागर के समुद्री मार्गों और दुनिया की खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा को लेकर भारत की प्रतिबद्धता एक अहम वजह पर आधारित है। यह क्षेत्र भारत की तरह दुनिया के प्रमुख खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में से एक है।

खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा, नाटो देशों की बढ़ी बेचैनी

बर्लिन, एजेंसी। जर्मन अखबार सुडड्यूश जिटुंग और पब्लिक ब्रॉडकास्टर एनडीआर व डब्लूडीआर की एक संयुक्त जांच के अनुसार, पश्चिमी खुफिया एजेंसियों और सैन्य आकलन बताते हैं कि रूस इस साल के अंत से पहले अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने की योजना बना रहा है।

रिपोर्ट में क्या बताया गया : सुडड्यूश जिटुंग की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में कई नाटो देशों के साथ साझा की गई इन जानकारियों से पता चलता है कि मॉस्को इस साल ही परमाणु विस्फोटकों से लैस एक उपग्रह (सैटेलाइट) लॉन्च करने की तैयारी में है। जर्मन अखबार के अनुसार, इस आकलन को पश्चिमी खुफिया एजेंसियों और रक्षा अधिकारियों का समर्थन मिला है, जिनमें जर्मन सशस्त्र बल (बुंडेसवेहर) और जर्मनी की संघीय खुफिया सेवा (बीएनडी) शामिल हैं।

रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा : हाल के हफ्तों में, बुंडेसवेहर (जर्मन सशस्त्र बलों) के विशेषज्ञों ने रूस की योजनाओं के बारे में वरिष्ठ जर्मन राजनेताओं को जानकारी दी है। इनमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस भी शामिल हैं। सुडड्यूश जिटुंग की रिपोर्ट के अनुसार, जर्मनी के संघीय रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने गोपनीयता का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारी अंतरिक्ष में हो रही वैश्विक घटनाओं और अन्य देशों की गतिविधियों पर लगातार और बारीकी से नजर रख रहे हैं।

इस बीच, रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टीएएसएस ने बताया है कि रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेन और नाटो के कदमों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, जिनमें मॉस्को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार कर सकता है।

रूस क्या आकलन करना चाहता है : टीएएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, मॉस्को जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ में राज्य की संप्रभुता और परमाणु हथियारः राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के अंतरराष्ट्रीय कानूनी पहलू शीर्षक वाले एक लेख में मेदवेदेव ने लिखा है कि किसी भी हमले को अधिकृत करने से पहले, रूस यह आकलन करता है कि क्या परमाणु जवाब, हुए नुकसान के अनुपात में है या नहीं।

टीएएसएस के अनुसार, मेदवेदेव ने कहा, कई मामलों में, हमारे खिलाफ एकजुट होकर खड़े पक्षों (यूक्रेन, नाटो देश और गठबंधन के बाहर के कई पश्चिमी देश) ने पहले ही ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं, जिनमें रूस परमाणु हमला करने की संभावना पर विचार कर सकता है। हालांकि, टीएएसएस ने बताया कि मेदवेदेव ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में संयम बरतने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति हमेशा सभी कारकों के व्यापक विश्लेषण और वास्तव में हुए नुकसान तथा जवाबी कार्रवाई के बीच उचित संतुलन को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाते हैं।

अमेजन के जंगल में 11 दिन भटकता रहा बुजुर्ग, रेस्क्यू टीम ने अल्जाइमर से पीड़ित को निकाला

रियो डी जनेरियो, एजेंसी। ब्राजील के अमेजन वर्षावन में 11 दिन तक अकेले जीवित रहने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति को बचाया गया है। अल्जाइमर से पीड़ित यह व्यक्ति अब मकापा शहर के एक अस्पताल में ठीक हो रहा है। बचाव कर्मियों ने उनकी इस आश्चर्यजनक कहानी का विवरण साझा किया है। 74 वर्षीय जनारिनो फरेरा डोस सैंटोस को पार्क रेंजरों और स्वयंसेवकों ने शुक्रवार को बचाया। उन्हें पूर्वोत्तर ब्राजील के मकापा से करीब 10 किलोमीटर दूर घने वर्षावन से निकाला गया।

बचाव कर्मियों ने बताया कि डोस सैंटोस जामुन खाकर और प्राकृतिक स्रोतों से पानी पीकर जीवित रहे। उन्होंने रात में आराम करने के लिए अकाई ताड़ के पत्तों से बिस्तर जैसी संरचनाएं भी बनाईं। पार्क रेंजर एनियल कार्डोसो ने बताया कि युवावस्था में डोस सैंटोस ने वर्षावन में काम किया था। इसलिए उन्हें जंगल में घूमना आता था। कार्डोसो और स्वयंसेवकों ने डोस सैंटोस के पैरों के निशान देखकर उन्हें खोजा। उन्होंने पाया कि वह गोल-गोल घूम रहे थे। पैरों के निशान का पीछा करते हुए बचाव दल को अकाई पत्तों से बना एक बिस्तर मिला। यह बिस्तर कम से कम चार दिन पुराना लग रहा था।

बाद में उन्हें एक और बिस्तर मिला जिसके पत्ते उसी सुबह ताड़ के पेड़ से तोड़े गए थे। कार्डोसो ने कहा कि तभी उन्हें लगा कि वह जीवित हो सकते हैं और पास ही होंगे। बचाव दल को डोस सैंटोस जंगल के घने हिस्से में मिले। वह नंगे पैर और केवल अंतर्वस्त्र पहने बैठे थे। कार्डोसो ने बताया कि डोस सैंटोस बात नहीं कर पा रहे थे। वह चल भी नहीं पा रहे थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। इस खोज अभियान में परिवार के सदस्य, स्वयंसेवक और सार्वजनिक सुरक्षा दल शामिल थे। उन्हें जंगल में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अग्निशमन कर्मियों और विशेष टीमों ने जमीन पर खोज की। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी निगरानी की गई। लापता व्यक्ति के संकेतों के लिए थर्मल कैमरों का भी उपयोग किया गया।

पाकिस्तान में भी लगे भूकंप के झटके: 4.1 रही तीव्रता; जमीन से 17 किलोमीटर नीचे था केंद्र

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान में मंगलवार सुबह भूकंप आया। इसकी तीव्रता 4.1 थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, भूकंप सुबह 7 बजकर 46 मिनट 31 सेकंड पर आया। भूकंप का केंद्र 28.221 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.777 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। इसकी गहराई जमीन से 17 किलोमीटर नीचे थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। फिलहाल इस जानकारी में किसी तरह के जान-माल के नुकसान का जिक्र नहीं है।

इससे पहले रविवार (22 नवंबर) को भी पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। यह भूकंप पाकिस्तान में अफगानिस्तान सीमा के पास आया। इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने बताया था कि



भूकंप का केंद्र अक्षांश 32.794ए उत्तर और देशांतर 69.745ए पूर्व पर था। एनसीएस ने इस घटना को समीक्षा की गई श्रेणी में रखा।

मंगलवार को दक्षिण एशिया के कई देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान शामिल हैं। नेपाल में सर्वाधिक 5.4 तीव्रता का भूकंप आया। धरती के भीतर सात प्लेट्स हैं, जो लगातार घूमती रहती हैं। जिस स्थान पर प्लेट्स की टक्कर होती है, उस जगह को फॉल्ट लाइन कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर स्थित टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने, आपस में टकराने या रगड़ खाने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब प्लेटों के टकराने से ज्यादा ऊर्जा निकलती है, तो धरती की सतह पर कंपन पैदा होता है। जिस स्थान पर प्लेट्स टकराती हैं, उस स्थान पर सबसे अधिक भूकंप का असर होता है। लेकिन जब भूकंप की तीव्रता अधिक होती है तो इसके झटके काफी दूर तक महसूस किए जाते हैं। वैज्ञानिक भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। जब भूकंप आता है, पृथ्वी के नीचे से ऊर्जा तरंगे बाहर आती हैं। उन्हें रिक्टर स्केल से मापा जाता है। इसके बाद ही यह पता लगता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी और इसका केंद्र कहां पर था। भूंकप की जांच रिक्टर स्केल से होती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी एपीसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है, उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा होता है। अगर भूकंप आता है, तो आप घर के अंदर हैं और बाहर नहीं निकल सकते हैं तो किसी मजबूत टेबल या किसी फर्नीचर के नीचे छिप जाएं। हालांकि, कंपन कम होने पर या बंद होने पर धीरे-धीरे घर से बाहर जरूर निकल जाएं।

कनाडा के बिजनेसमैन और उनकी पार्टनर की हत्या के मामले में दो अमेरिकियों को उम्रकैद, डोमिनिका में सुनाई गई सजा

रोसेउ , एजेंसी। कैरेबियाई देश डोमिनिका की एक अदालत ने साल 2023 में हुए कनाडाई बिजनेसमैन डैनियल लैंगलोइस और उनकी पार्टनर डोमिनिक मार्चंड की हत्या मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी रोसेउ की अदालत ने सोमवार को दो अमेरिकी नागरिकों जोनाथन लेहरर और रॉबर्ट स्नाइडर जूनियर को दो-दो बार उम्रकैद की सजा सुनाई है। जज ने इन हत्याओं को बिना किसी उकसावे के किया गया हमला बताया और कहा कि यह मामला दुर्लभ से भी दुर्लभ (रेयरेस्ट ऑफ द रेयर) की श्रेणी में आता है। दोनों दोषियों को हत्याओं के कुछ दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इस साल 28



जुलाई को अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। हालांकि, दोषियों के वकील ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है।

क्या था पूरा मामला : डैनियल लैंगलोइस ने मॉन्ट्रियल स्थित सॉफ्टइमेज नाम की कंपनी की स्थापना की थी। यह कंपनी अपनी 3ड एनीमेशन तकनीक के लिए जानी जाती है। जिसका इस्तेमाल जुरासिक पार्क, द मैट्रिक्स और टाइटैनिक जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में किया गया है। वह और उनकी पार्टनर मार्चंड दक्षिणी डोमिनिका में कौलीबरी रिजनाम के एक इको-रिसॉर्ट के मालिक भी थे। यह जोड़ा कई दिनों से लापता था। 1 दिसंबर 2023 को रिसॉर्ट के पास गैलियन इलाके में एक जली हुई कार के अंदर उनके शव मिले। न्यू जर्सी में जन्मे चॉकलेट निर्माता लेहरर की जमीन रिसॉर्ट के बगल में थी, जबकि मैकेनिक स्नाइडर उनके लिए काम करता था। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, लेहरर और लैंगलोइस के बीच रिसॉर्ट तक जाने वाली एक सड़क को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा था, जो लेहरर की जमीन से होकर गुजरती थी और रिसॉर्ट तक जाने का रास्ता थी। साल 2019 में, एक जज ने लेहरर को आदेश दिया था कि वह इस सड़क को आम लोगों के लिए खुला रखे और यह सुनिश्चित करे कि लैंगलोइस के पास आने वाले लोग बिना किसी रोक-टोक के इसका इस्तेमाल कर सकें। हालांकि, लेहरर के परिवार के प्रतिनिधियों ने इस बात से इनकार किया है कि सड़क को लेकर चल रहा विवाद इन हत्याओं की वजह था। पिछले हफ्ते परिवार की प्रवक्ता सिल्वी डेस्लौरियर्स ने लैंगलोइस की मां की ओर से एक भावुक बयान जारी किया।* और उनकी मौत के लगभग तीन साल बाद परिवार उन्हें अंतिम विदाई दे सका है।

दक्षिण कोरिया के डिफेंस जोन में घुसे रूसी विमान; द्वीप पर 3 मिनट में अलर्ट जारी, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने का आदेश



सोल , एजेंसी। दक्षिण कोरिया ने रूसी विमानों के हवाई रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अलर्ट जारी किया सियोल, 24 नवंबर (एपी) रूस के कई विमानों ने कोरियाई प्रायद्वीप एवं जापान के बीच समुद्री क्षेत्र के ऊपर दक्षिण कोरिया के हवाई रक्षा पहचान क्षेत्र में उड़ान भरी जिसके बाद देश के पूर्वी हिस्से में स्थित एक द्वीप पर अलर्ट जारी किया गया।

दक्षिण कोरिया की सेना ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पहले जारी खबरों में कहा गया था कि विमानों ने देश के संप्रभु हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया लेकिन दक्षिण कोरियाई सेना ने बाद में इन खबरों में संशोधन कर कहा कि विमानों ने उसके हवाई रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश किया। हवाई रक्षा पहचान क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से निर्धारित वह क्षेत्र होता है जिसमें उड़ान भरने वाले विमानों की पहचान और उनकी गतिविधियों की निगरानी की जाती है। यह क्षेत्र किसी देश के संप्रभु हवाई क्षेत्र से बाहर अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र तक भी फैला हो सकता है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने अपने बयान में गृह एवं सुरक्षा मंत्रालय तथा स्थानीय प्रांतीय सरकार की ओर से पहले दी गई उस जानकारी में सुधार किया जिसमें कहा गया कि विदेशी विमानों ने दक्षिण कोरिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और ये विमान संभवतः रूस या उत्तर कोरिया के थे। सुरक्षा मंत्रालय ने सुबह करीब सात बजकर 52 मिनट पर उल्लुंग द्वीप के निवासियों को भूमिगत केंद्रों या इमारतों में शरण लेने का आदेश दिया लेकिन तीन मिनट बाद यह कहते हुए आदेश वापस ले लिया कि विमान खतरे वाले क्षेत्र से बाहर चले गए हैं। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि रूसी विमानों के वहां से जाने से पहले दक्षिण कोरिया ने हर प्रकार की संभावित स्थिति से निपटने के लिए अपने लड़ाकू विमान रवाना किए थे। उन्होंने तत्काल यह नहीं बताया कि कितने रूसी विमानों का पता चला था और वे किस प्रकार के विमान थे। वर्ष 2022 में भी उल्लुंग द्वीप के निवासियों में उस समय दहशत फैल गई थी, जब दोनों कोरियाई देशों के बीच बढ़ते तनाव के मध्य उत्तर कोरिया ने समुद्र में 20 से अधिक मिसाइल दागी थीं।

एनवीडिया मुख्यालय पहुंचे हुआंग: कर्मचारियों ने तालियों और नारों से किया स्वागत; मस्क बोले- सब चाहते थे वापसी

कैलिफोर्निया, एजेंसी। एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेनसन हुआंग की कंपनी में वापसी पर कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कैलिफोर्निया स्थित कंपनी के मुख्यालय पहुंचने पर कर्मचारियों ने जेनसन के लिए तालियां बजाईं और नारे भी लगाए। हुआंग की बहाली पर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एनवीडिया में उनके जानने वाले सभी कर्मचारी हुआंग की वापसी चाहते थे। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें एनवीडिया के कर्मचारी हुआंग का स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, एनवीडिया में जिन लोगों को मैं जानता हूं, वे सभी जेनसन को वापस चाहते थे और यह वीडियो सब कुछ दिखा रहा है।

पहले किया इनकार, फिर एनवीडिया ने दोबारा बनाया सीईओ : एनवीडिया ने सोमवार को घोषणा की थी कि जेनसन हुआंग को तत्काल प्रभाव से कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर बहाल कर दिया गया है। उन्हें निदेशक मंडल में भी फिर से शामिल किया गया है। कंपनी के बोर्ड ने बयान में बताया कि हुआंग के साथ कई दौर की बातचीत और बैठकों के बाद सर्वसम्मति से उनकी बहाली का



फैसला लिया गया। बोर्ड ने उनके स्पष्ट विचार रखने के तरीके और कंपनी का नेतृत्व करने की क्षमता पर भरोसा जताया।

मस्क और ट्रंप ने फैसले का किया समर्थन : हुआंग की वापसी पर एलन मस्क ने इससे पहले भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि गलती सुधार ली गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एनवीडिया के फैसले को शानदार बताया और कंपनी को बधाई दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि एनवीडिया ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन से जुड़े आरोपों के बीच उन्होंने कंपनी के निदेशक मंडल को हुआंग की स्थिति को लेकर पर्याप्त आश्वासन दिया था। अमेरिकी समाचार चैनल सीएनबीसी से बातचीत में ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्होंने बोर्ड को आश्वासन दिया था कि हुआंग के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इस पर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अभियोजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन यह जरूर बताया था कि प्रशासन के मुताबिक हुआंग बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बोर्ड को पर्याप्त भरोसा दिया था।

डेमोक्रेटिक नेता ने फैसले की आलोचना की : हालांकि, अमेरिकी संसद में डेमोक्रेटिक नेता और प्रतिनिधि सभा के संभावित स्पीकर हकीम जेफ्रीज ने हुआंग की बहाली की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस फैसले को अनुचित, गैर-जिम्मेदाराना और समझ से परे बताया। जेफ्रीज ने कहा कि कांग्रेस एनवीडिया के कथित कारोबारी अनियमितताओं और वाणिज्य विभाग के प्रमुख हॉवर्ड लुटनिक के कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग की व्यापक जांच से पीछे नहीं हटेगी। एक्स पर जारी बयान में जेफ्रीज ने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन निजी आर्थिक लाभ के लिए अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से समझौता कर रहा है। जेफ्रीज ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में कड़े निर्यात नियंत्रण प्रावधान शामिल करने की मांग भी की। उनका कहना है कि शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक का इस्तेमाल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य विरोधी ताकतों की ओर से नहीं किया जाना चाहिए।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

असम में डीआईजी और एसएसपी में जमकर हुई मारपीट

● सीएम ने पल्ला झाड़ा कहा- ये आपस का मामला है

कोकराझार, एजेंसी। असम के कोकराझार जिले में देर रात आयोजित एक पार्टी के दौरान दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के बीच विवाद मारपीट तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में कोकराझार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अक्षत गर्ग घायल हो गए हैं। इस मामले पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे निजी विवाद बताया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह घटना पिछले वीकेंड की है। कोकराझार के सराईखोला स्थित सातवीं असम पुलिस बटालियन परिसर में अक्षत गर्ग ने एक पार्टी का आयोजन किया था। इसी दौरान अक्षत गर्ग और वेस्टर्न रेंज के डीआईजी वाईटी ग्यात्सो के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों अधिकारियों के बीच हाथापाई हो गई, जिसमें एसएसपी अक्षत गर्ग को कई चोटें आईं। हालांकि, असम पुलिस मुख्यालय ने अभी तक इस कथित घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और न ही इस संबंध में कोई बयान जारी किया है। घटना किन परिस्थितियों में हुई और पार्टी में मौजूद अन्य लोगों की क्या भूमिका थी, इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें घटना की जानकारी है, लेकिन यह एक निजी पार्टी में हुआ विवाद था और उस समय दोनों अधिकारी ड्यूटी पर नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर यह घटना ड्यूटी के दौरान हुई होती तो सरकार हस्तक्षेप करती और जरूरी कदम उठाती, लेकिन निजी मामले में सरकार कुछ नहीं कह सकती।

दलाई लामा को लुटियंस दिल्ली में सरकारी बंगला

● विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर किया आवंटन, तिब्बती नेतृत्व ने फैसले का किया स्वागत

नई दिल्ली, एजेंसी। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को राजधानी दिल्ली के लुटियंस क्षेत्र में सरकारी आवास आवंटित किया गया है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर दलाई लामा के कार्यालय 'गादेन फोडरंग ट्रस्ट' को पंडित रविशंकर शुक्ला लेन स्थित टाइप-7 सरकारी बंगला आवंटित किया है। हालांकि, इस संबंध में मंत्रालय की ओर से अभी आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक, सरकारी आवास का आवंटन आम तौर पर तीन वर्ष के लिए किया जाता है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसकी अवधि बढ़ाने का प्रावधान भी होता है। इस आवास से दलाई लामा के दिल्ली दौरों के दौरान उनके ठहरने के लिए एक स्थायी व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। संसद की स्पीकर डोलमा त्सेरिंग ने इसे अच्छी खबर बताते हुए कहा कि इससे दलाई लामा के लिए राष्ट्रीय राजधानी में आना और यहां ठहरना अधिक सुविधाजनक होगा। निर्वासित तिब्बती संसद की स्थायी समिति के सदस्य चोदक ग्यात्सो ने भी फैसले को सम्मान की बात बताया। उन्होंने कहा कि तिब्बतियों के पास अपना देश नहीं होने के दौर में भारत ने उन्हें शरण दी और धर्मशाला में बसने, स्कूल तथा अन्य संस्थान स्थापित करने में सहयोग किया। उनके मुताबिक, इन संस्थानों ने तिब्बती संस्कृति और पहचान को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।



मणिपुर में केसीपी से जुड़े पांच उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और गोला-बारूद बरामद

इंफाल, एजेंसी। मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में सुरक्षा बलों ने पिछले दो दिनों में अलग-अलग अभियानों के दौरान प्रतिबंधित संगठन केसीपी (पीडब्ल्यूजी) से जुड़े पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि अभियान के दौरान हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, पुलिस कमांडो और असम राइफल्स की संयुक्त टीम ने सोमवार को पटसोई थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की।

बीजेपी-अकाली दल गठबंधन को सचिन पायलट ने बताया, हताशा का गठबंधन

-कहा- दोनों दलों के अलग होने के कारण आज तक स्पष्ट नहीं, जनता तय करेगी बेहतर विकल्प

चंडीगढ़ , एजेंसी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के फिर साथ आने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब मामलों के प्रभारी सचिन पायलट ने दोनों दलों के गठबंधन को 'हताशा का गठबंधन' बताया। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में दोनों दलों के लिए राजनीतिक जगह नहीं बची है।



भाजपा और अकाली दल ने मंगलवार को गठबंधन की घोषणा की थी। छह साल बाद शिअद की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में वापसी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि गठबंधन में मुख्यमंत्री पद शिरोमणि अकाली दल के पास रहेगा और वह 'बड़े भाई' की भूमिका में होगा।

पायलट ने कहा कि यह समझौता और हताशा का गठबंधन है, क्योंकि दोनों दलों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि छह साल पहले वे किन कारणों से अलग हुए थे। उन्होंने सवाल किया कि वे कौन से कारण थे, जिनकी वजह से भाजपा और शिअद ने अपना पुराना गठबंधन तोड़ा था।

उन्होंने भाजपा से सवाल करते हुए कहा कि क्या केंद्र सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी दी है और क्या तीन कृषि कानूनों को लेकर माफी मांगी गई है। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली की सीमाओं पर जान गंवाने वाले किसानों के प्रति अकाली दल के रुख पर भी सवाल उठाया।

पायलट ने कहा कि दोनों दलों का फिर साथ आना उनकी अपनी पसंद है और जनता ही तय करेगी कि उसके लिए बेहतर विकल्प कौन है। गौरतलब है कि शिअद ने सितंबर 2020 में तीन कृषि कानूनों को लेकर भाजपा के साथ अपना 24 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। बाद में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे।

सेना पर हमले की थी साजिश में आतंकी वांटेड उजैद गिरफ्तार

● बम वाली जैकेट पहनकर आर्मी का चेकपोस्ट उड़ाने का था प्लान

मेरठ, एजेंसी। यहां एक बड़ी कार्रवाई के तहत जम्मू-कश्मीर से वांटेड संदिग्ध आतंकी उजैद को स्वॉट टीम ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर उजैद और उसके साथी किशोरों को आत्मघाती आतंकी (फिदायीन) बनाने का मॉड्यूल चला रहे थे। इनका मकसद जम्मू-कश्मीर में आर्मी कैंपों और आर्मी काफिले पर उरी और पुलवामा जैसे बड़े हमले करना था। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बनियापाड़ा, कोतवाली मेरठ निवासी उजैद की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि वह फिदायीन हमलों में इस्तेमाल होने वाली एक्सप्लोसिव जैकेट लेने के लिए गुरैज वैली के रास्ते पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए जाने वाला था। उजैद उसी आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था जिसका खुलासा पिछले साल नवंबर में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने किया था। उस दौरान साजिद नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि उजैद पिछले 10 माह से फरार चल रहा था। उजैद और साजिद सहित कुछ युवक सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर और आईएसआई एजेंट के संपर्क में आए थे। इन्हें किशोरों को आत्मघाती हमलों के लिए तैयार करने और आतंकी मॉड्यूल में शामिल करने का टास्क दिया गया था। पकड़ा गया उजैद पाकिस्तानी आतंकी मौलाना मसूद अजहर, तारिक मसूद और डॉ इशरार का प्रशंसक था और उनके वीडियो देखता था। इन्हीं वीडियो पर कमेंट करने के दौरान वह पाकिस्तानी हैंडलर की नजर में आया। इंस्टाग्राम, सेशन ऐप और सिग्नल ऐप पर 'ट्यूशन-40' और 'ब्रिगेड' नाम से ग्रुप बनाकर उजैद और अन्य को जोड़ा गया था। इन ग्रुपों में पीओके से आतंकी अमीर हमजा, पाकिस्तान के पंजाब से अबू मुसाब और पीओके से फुरकान व कामरान जैसे कई आईएसआई एजेंट जुड़े थे। इन ऐप्स पर बने ग्रुपों में ही हमलों की योजना बनाई गई थी। सेशन ऐप पर बने 'ब्रिगेड' ग्रुप में साजिद ने लिखा था कि वह बम वाली जैकेट पहनकर आर्मी का चेकपोस्ट उड़ा देगा, और 100 प्रतिशत देगा। दूसरे साथी द्वारा जैकेट के बारे में पूछने पर पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर ने जवाब दिया था कि वे इसे घर में ही बना लेंगे।

सीजेपी नेता सौरभ दास की विदेश यात्रा पर रोक

● दीपके की फॉड सलाह पर छिड़ा विवाद

नई दिल्ली, एजेंसी। काम्पैक्ट जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरभ दास को विदेश यात्रा से रोके जाने पर विवाद गहरा गया है। इस घटना के बाद पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने सरकार पर तंज कसते हुए दास को कोई बड़ा फॉड करने की सलाह दे डाली, ताकि उन्हें भी नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों की तरह देश से बाहर जाने दिया जाए। दीपके ने दास के पासपोर्ट पर उठ रहे सवालों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। सौरभ दास ने सोमवार को आरोप लगाया था कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के बुलावे पर लंदन जाने से रोका गया है। उन्होंने एक वीडियो साझा कर बताया कि उन्हें पैनल चर्चा और लेक्चर के लिए न्योता मिला था, लेकिन सरकार ने उन्हें यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया। सीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर लिखा, विजय माल्या ने 9 हजार करोड़ रुपये का फॉड किया, नीरव मोदी ने 6 हजार 498 करोड़ रुपये का फॉड किया, और मेहुल चोकसी ने 7 हजार 80 करोड़ रुपये का फॉड किया। इन सभी तीनों को देश छोड़कर भागने दिया गया। सौरभ दास भाई, कोई बड़ा फॉड कर अगर बाहर जाना है तो। उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि काश सौरभ ने बैंक लूटा होता या फॉड किया होता, फिर सरकार उसे जरूर लंदन जाने देती। दीपके ने सौरभ दास के पासपोर्ट के मुद्दे पर भी सरकार से सवाल किया। उन्होंने लिखा, सौरभ के पासपोर्ट में गड़बड़ियां? उसका पासपोर्ट तो इसी सरकार ने साल 2019 में जारी किया था। उन्हें 7 साल से कोई गड़बड़ियां नहीं मिली हैं, लेकिन सीजेपी के गठन और सौरभ दास के उसके सबसे बड़े चेहरों में से एक बनने के बाद अचानक मिलने लगीं। उन्होंने यह भी कहा कि दास को हवाई अड्डे पर रोक लिया गया और बताया गया कि वह भारत से बाहर नहीं जा सकता। दीपके ने प्रश्न किया, एक भारतीय विदेश यात्रा क्यों नहीं कर सकता? क्या वह अपराधी है? दास द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने कोई घोटाला या धोखाधड़ी नहीं की। दास ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम ऑक्सफोर्ड यूनियन में 1 दिसंबर को था, जिसमें उन्हें और सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह को आमंत्रित किया गया था। छात्रों ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और क्वीन मैरी विश्वविद्यालय में भी अन्य कार्यक्रमों की योजना बनाई थी।

पश्चिम बंगाल: तेजी से बढ़ा एनसीपीआई का दबदबा, टीएमसी में फिर टूट

कोलकाता , एजेंसी । पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक नया सियासी समीकरण आकार ले रहा है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कभी मजबूत गढ़ माने जाने वाले ग्रामीण इलाकों में अब नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) तेजी से अपनी पकड़ बना रही है। इस पार्टी में पहले से ही सायोनी घोष, सुदीप बंद्योपाध्याय, शताब्दी रॉय और यूसुफ पठान जैसे चर्चित नेता शामिल हो चुके हैं। तृणमूल के 20 बागी सांसदों के एनसीपीआई में शामिल होने के बाद अब पंचायत स्तर पर भी पार्टी का विस्तार हो रहा है।

उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक कई पंचायत प्रतिनिधियों के पाला बदलने से ममता बनर्जी के सामने संगठनात्मक चुनौती खड़ी हो गई है। इस घटनाक्रम ने जहां टीएमसी के ग्रामीण आधार पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रणनीति को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है।

इस बदलाव की सबसे अहम बात यह है कि एनसीपीआई कोई पुरानी या बंगाल में मजबूत संगठनात्मक आधार वाली पार्टी नहीं है। यह केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। इसके बावजूद पंचायतों में लगातार हो रहे दलबदल ने उसे राज्य की राजनीति में चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एनसीपीआई का यह उत्थान चौंकाने वाला है, क्योंकि हाल तक पश्चिम बंगाल में इसकी न के बराबर संगठनात्मक उपस्थिति थी। तृणमूल कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार के बाद मची राजनीतिक उथल-पुथल का यह सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है। इसने बड़ी संख्या में चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी ओर आकर्षित किया है और कई ग्रामीण निकायों में सत्ता का संतुलन बदल दिया है। ताजा घटनाक्रम में सबसे बड़ा असर उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट संसदीय क्षेत्र में दिखाई दे रहा है।

एनसीपीआई का दावा है कि उसने तृणमूल के कब्जे वाली 13 ग्राम पंचायतों और दो पंचायत समितियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इस इलाके में संदेशखाली और मीनाखान जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जहां से कई स्थानीय जनप्रतिनिधि एनसीपीआई में शामिल हुए हैं। मीनाखान पंचायत समिति में 23 सदस्यों में से 13 ने तृणमूल छोड़कर एनसीपीआई का दामन थाम लिया, जिनमें समिति के उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। इसी तरह संदेशखाली-ढ्ढ पंचायत समिति के 24 सदस्यों में से 17 ने एनसीपीआई का रुख किया है, जबकि संदेशखाली-ढ्ढ की नजात-2 ग्राम पंचायत में 26 में से 19 सदस्य पार्टी छोड़कर चले गए हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले की गोलपोखर-द्वितीय पंचायत समिति में भी अध्यक्ष समेत 16 सदस्य एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं।

एनसीपीआई का यह विस्तार तृणमूल की चुनावी हार और उसके बाद पार्टी के संसदीय खेमे में हुई टूट के बाद हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के 27 लोकसभा सदस्यों में से 20 सदस्य अलग होकर



एनसीपीआई में शामिल हो गए थे, साथ ही उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी। तृणमूल कांग्रेस ने एनसीपीआई को भाजपा के मोहरे के तौर पर काम करने का आरोप लगाया है। टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने कहा, भाजपा अपनी बी-टीम और सी-टीम ला रही है। जो लोग दल बदलकर गए हैं, वे भाजपा के एजेंट हैं। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने भी आरोप लगाया कि एनसीपीआई का सामने आना, बंगाल में भाजपा के विस्तार को आसान बनाने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है।

संविधान दिवस पर लखनऊ में कांग्रेस की रैली आज, खड़गे होंगे शामिल

● प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम, आराधना मिश्रा बोलीं—संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प मजबूत करेंगे

लखनऊ,एजेंसी। संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को लखनऊ में कांग्रेस की ओर से रैली और कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम में शामिल होना प्रदेश कांग्रेस के लिए गर्व और उत्साह का विषय है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे कांग्रेस सड़क से लेकर प्रदेश स्तर तक और मजबूत करेगी। इसी संकल्प के साथ 26 नवंबर को रैली आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर मिश्रा ने कहा कि करीब साढ़े तीन घंटे तक बैठक हुई और बातचीत सकारात्मक रही। उन्होंने इसे गठबंधन के लिए अच्छी शुरुआत बताया। मिश्रा ने कहा कि गठबंधन को पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी 30 फीसदी तक बढ़ाएगी केरल सरकार

-महिला अधिकारी मादक पदार्थों के खिलाफ अभियानों में कर रही अच्छा प्रदर्शन

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। केरलम सरकार ने राज्य में अपराध पर लगाम लगाने और जांच प्रक्रिया को तेज करने के लिए पुलिस बल में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने बताया कि सरकार चरणबद्ध भर्ती के जरिए पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को 30 फीसदी तक बढ़ाएगी। मंत्रिमंडल के फैसले के तहत, भविष्य में होने वाली भर्तियों में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 7:3 रखा जाएगा। मंत्री ने मलप्पुरम अपराध शाखा इकाई कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिला अधिकारी अपराध का पता लगाने और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियानों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। वर्तमान में राज्य भर के 63 थानों में एसएचओ के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ ही अपराध शाखा और सतर्कता शाखाओं की कार्यकुशलता में सुधार के लिए भी बदलाव किए जाएंगे। गृह मंत्री ने बताया कि अपराध शाखा और सतर्कता विभाग में अब नियुक्तियां पूरी तरह योग्यता के आधार पर की जा रही हैं। जांच में रुचि और दक्षता रखने वाले अधिकारियों का चयन विशेष परीक्षा के जरिए किया जाता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक यह परीक्षा पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के परामर्श से तैयार की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन विशेष शाखाओं का उद्देश्य नियमित पुलिस बल में काम के बोझ के कारण दरकिनार कर दिए गए अधिकारियों को जगह देना नहीं है।

वर्तमान में राज्य में अपराध शाखा फिलहाल 2,763 अहम मामलों की जांच कर रही है, जिनमें 321 मामले अकेले 2026 में दर्ज किए गए हैं। विभाग की प्राथमिकता निर्धारित समयसीमा के भीतर जांच पूरी करना है। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में मादक पदार्थों के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए



शुरू किया गया 'ऑपरेशन तूफान' काफी सफल रहा है और इसके लागू होने के बाद आपराधिक मामलों में 35 फीसदी की कमी आई है। यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।

अब भारत को न्योता देगा पाकिस्तान, एससीओ बैठक में शरीक होंगे जयशंकर?

नई दिल्ली, एजेंसी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में आई तल्खी के बावजूद, दोनों देश एक बार फिर बहुपक्षीय मंच पर संपर्क साधने की तैयारी में हैं। पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के तहत अगले साल की शुरुआत में होने वाली संस्कृति मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है।

यह बैठक पाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित होगी। भारत इस न्योते पर क्या रुख अपनाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में एससीओ की पहली सभ्यतागत संवाद बैठक में पाकिस्तान को न्योता दिया था, जिसमें पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक भी शामिल हुए थे। अब पाकिस्तान की ओर से भारत को निमंत्रण भेजा जा रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस बैठक में किस स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से किसी भी भारतीय मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। हालांकि, विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आलोक डिमरी ने सितंबर 2025 में



एससीओ के राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था।

संस्कृति मंत्रियों की बैठक को राजनीतिक स्तर पर कम संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रतिबद्धताएं सीमित होंगी, जबकि विदेश या रक्षा मंत्रियों की बैठकें अधिक राजनीतिक प्रतिक्रिया पैदा कर सकती हैं। संस्कृति मंत्रियों की बैठक के बाद, पाकिस्तान एससीओ के विदेश और रक्षा मंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठकों के साथ-साथ अगस्त 2026 में राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन में आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उनका इस्लामाबाद जाना बेहद मुश्किल नजर आता है।

ऐसे में, विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उन्होंने 2025 में कजाकिस्तान में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की जगह भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और अक्टूबर 2024 में भी वे एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पाकिस्तान गए थे (पहलगाम हमले से पहले)। इससे भारत की संगठन के प्रति प्रतिबद्धता भी बनी रहेगी और पाकिस्तान को लेकर उसकी मौजूदा नीति में किसी नरमी का संदेश भी नहीं जाएगा। भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को भारत- पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। नई दिल्ली में मुसादिक मलिक की मेजबानी के बाद भारत ने साफ किया था कि सिंधु जल संधि पर उसका रुख नहीं बदला है। भारत का जोर सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर ठोस प्रगति पर है और वह ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहता है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों के सामान्य होने का संदेश जाए। पाकिस्तान के साथ संबंधों में नरमी की गुंजाइश तभी बन सकती है, जब सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के रुख में बुनियादी बदलाव दिखाई दे।

पंजाब में शुक्रवार को ब्लैकआउट, रात 8 बजे बजेगा खतरे का सायरन

● राज्य के सभी जिलों में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल

चंडीगढ़, एजेंसी । पंजाब में नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को परखने के लिए 27 नवंबर को रात आठ बजे राज्य के सभी जिलों में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत होने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य आपात स्थिति में प्रशासन और नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारियों को परखना है। अभ्यास की शुरुआत एयर रेड चेतावनी सायरन से होगी। दो मिनट तक ऊंची और धीमी आवाज वाला सायरन बजाया जाएगा। इसके बाद संबंधित जिलों के उपायुक्त और नागरिक सुरक्षा नियंत्रक चिन्हित क्षेत्रों में सांकेतिक ब्लैकआउट लागू करेंगे। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से गैर-जरूरी रोशनी बंद रखने को कहा गया है। प्रशासन के अनुसार अस्पताल, फायर ब्रिगेड और अन्य आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहेंगी।

यूपी की 11 सीटों को लेकर सपा-कांग्रेस में घमासान

ये वो सीटें हैं जहां सपा खुद को कमजोर मानती है

लखनऊ, एजेंसी । समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों के लिए सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध गहरा गया है। सपा ने कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 11 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, जहां सपा संगठनात्मक रूप से खुद को अपेक्षाकृत कमजोर मानती है। इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, खासकर अमेठी और रायबरेली जैसी पारंपरिक सीटों पर कम हिस्सेदारी को लेकर। सपा के प्रस्ताव में शामिल 20 अतिरिक्त सीटों के क्षेत्रीय बंटवारे पर गौर करें तो, इनमें सबसे अधिक 11 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। सपा का मानना है कि इन सीटों पर वह अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में है। ये सभी सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीती थीं। इनमें से सात सीटों पर तब राष्ट्रीय लोकदल (रालोद), जो उस समय सपा गठबंधन का हिस्सा था, दूसरे स्थान पर रही थी। दो सीटों पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) दूसरे स्थान पर रही, जबकि दो सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद दूसरे स्थान पर रही थी। मध्य यूपी की दो प्रस्तावित सीटों में से बिलग्राम-मल्लावां में सपा दूसरे स्थान पर थी, जबकि गोविंद नगर सीट पर उसे 80,896 वोटों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। पूर्वी यूपी की सातों प्रस्तावित सीटों पर भी 2022 में सपा दूसरे स्थान पर रही थी, हालांकि सभी पर एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इनमें छह सीटें भाजपा ने और एक सीट नानपारा अपना दल (सोनेलाल) ने जीती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर शहर सीट भी इस सूची में शामिल है। सपा के 26 सीटों के प्रस्ताव से कांग्रेस नेताओं में भारी नाराजगी है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने इस प्रस्ताव पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सवाल उठाया कि अमेठी और रायबरेली जैसी पारंपरिक सीटों पर पार्टी को केवल एक सीट की पेशकश कैसे की जा सकती है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को केवल 26 सीटों की सूची कैसे दी जा सकती है। कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वह इस प्रस्ताव पर जल्द ही अपनी औपचारिक प्रतिक्रिया देगी। सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को हुई एक बैठक में दोनों दलों के नेताओं के बीच तीखी बहस भी हुई। सीटों के बंटवारे पर बातचीत फिलहाल जारी है। कांग्रेस ने पहले 131 सीटों की मांग रखी थी, जिसे घटाकर 120 कर दिया है, जबकि सपा का प्रस्ताव 26 सीटों पर ही अटका है। ऐसे में दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति बनना अभी भी दूर की कौड़ी लग रही है।